

संयुक्त किसान मोर्चा ने किया आज भारत बंद का ऐलान

कब से कब तक रहेगा बंद, वादों को पूरा नहीं करने पर यह बंद बुलाया

नई दिल्ली, 15 फरवरी 2024 (ए)। किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन ने मजदूर यूनियनों के साथ मिलकर 16 फरवरी को भारत बंद (ग्रामीण) का ऐलान किया है। भाकियू के बंद भारतीय किसान यूनियन (अं) गुट का भी समर्थन है। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से पहले किसान आंदोलन के समय किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर यह बंद बुलाया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने समान विचारधारा वाले सभी किसान संगठनों से एकजुट होने और केंद्रीय ट्रेड यूनियन की तरफ से बुलाए गए 16 फरवरी के ग्रामीण भारत बंद में भाग लेने का आग्रह किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा का 16 तारीख को भारत बंद और 14 फरवरी को 'दिल्ली चलो' कार्यक्रम पहले से घोषित है। सदस्यों पर हमारा आंदोलन 16 तारीख से फिर



शुरू हो रहा है। कई ट्रक असोसिएशन भी किसानों के समर्थन में हैं।
मनरेगा का काम भी बंद रहेगा
संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार भारत

बंद सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। किसानों का कहना है कि भारत बंद के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट दफ्तर, गांव की दुकानों

के साथ ही कृषि गतिविधियां और मनरेगा के तहत काम भी बंद रहेगा। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट एक्सेस भी बंद कर दिया जाएगा। किसान संगठनों

का कहना है कि बंद के दौरान एंबुलेंस, शादी वाले वाहन परीक्षा देने जा रहे छात्रों, मेडिकल दुकानों प्रभावित नहीं होगा।

भारत बंद के दौरान क्या बैंक बंद रहेंगे ?

फिलहाल, बैंक कल खुले रहेंगे और सामान्य रूप से काम करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अवकाश मैट्रिक्स में यह भी कहा गया है कि बैंक खुले रहेंगे। फरवरी महीने में भारत में बैंक 10 दिन बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार भी शामिल है। हालांकि, कुछ छुट्टियां राज्य-विशिष्ट हैं। यानी, केवल कुछ ही राज्य या क्षेत्र ऐसी तारीखों पर बैंक छुट्टियां मनाते हैं। किसान देशभर के प्रमुख मार्गों पर चक्का जाम करना चाहते हैं। भारत बंद के दौरान किसान पंजाब रोडवेज को चार घंटे के लिए बंद करना चाहते हैं।

गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग

बता दें कि यूपी गेट पर दिल्ली में किसानों के प्रवेश को देखते हुए फ्लाईओवर के बगल से गुजरने वाले रास्ते पर दिल्ली पुलिस ने दो दिन से बैरिकेडिंग कर रखी है। सीमेंट और कटिले तारों से रास्ते को बंद करके रखा गया है। वहीं, 16 फरवरी को किसानों ने अपनी अनगिनत मांगों को लेकर भारत बंद का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन (अं) के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा ने बताया कि 16 फरवरी को भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, उन्होंने इसका समर्थन किया है। उनके साथ ही अन्य किसान संगठन भी भारत बंद को लेकर यूपी गेट पहुंचे हैं।

ट्रेड यूनियनों भी होंगी शामिल

किसानों के 16 फरवरी को भारत बंद के ऐलान के बाद से यूपी गेट पर और ज्यादा चौकसी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि किसान इस दिन बॉर्डर पर जरूर पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी अखबार इंडी की रिपोर्ट के अनुसार, नुकड़ नाटकों, संगीत और कविताओं के माध्यम से प्रदर्शनकारियों की मांगों और श्रमिकों और किसानों की दुर्दशा पर जोर दिया जाएगा। भारत बंद में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों ने पिछली पेंशन योजना को समाप्त करने और आठवें वेतनमान आयोग की स्थापना करने का अपना इरादा घोषित किया है।

क्या है किसानों के तीन दिन का प्लान

किसान नेता गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा, आज तीन निर्णय लिए गए, पहला यह है कि हम कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हरियाणा को 3 घंटे के लिए टोल फ्री रखेंगे... परसों ट्रेक्टर रैली होगी हर तहसील में परेड की जाएगी और 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से सभी किसान और मजदूर संगठनों की संयुक्त बैठक होगी... उसी बैठक में आगे के फैसले लिए जाएंगे।

सक्षिप्त खबरें

टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती का इस्तीफा

कोलकाता, 15 फरवरी 2024 (ए)। जदवपुर से तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वे पार्टी स्थानीय नेताओं के साथ मतभेद के चलते यह फैसला ले रही हैं। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। मिमी चक्रवर्ती ने अपना इस्तीफा पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी को भेजा है।

हेमंत सोरेन की रिमांड पूरी, भेजे गए जेल

रांची, 15 फरवरी 2024 (ए)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर लगाई रोक

» चंदे की जानकारी न देना असंवैधानिक,
» वे आरटीआई का भी उल्लंघन

नई दिल्ली, 15 फरवरी 2024 (ए)। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। हालांकि पीठ में दो अलग विचार



रहे, लेकिन पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसबीआई बैंक को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। चुनावी बॉन्ड योजना के अनुसार, चुनावी बॉन्ड भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी

व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (ए) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत वोट पाने वाले दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है। कोर्ट ने मामले में 31 अक्टूबर से नियमित सुनवाई शुरू की थी। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की

अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने की। इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से दलीलें दी गईं। कोर्ट ने सभी पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इस योजना को सरकार ने दो जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। इसके मुताबिक, चुनावी बॉन्ड को भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई की ओर से खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के पात्र हैं। शर्त बस यही है कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट मिले हों। चुनावी बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा।

अपने ही गढ़ अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा गांधी परिवार

नई दिल्ली, 15 फरवरी 2024 (ए)। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को यहां अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसका मतलब यह है कि सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगीं। ऐसे में रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को इस बार रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने यह कहकर विपक्षी गठबंधन की चिंताएं बढ़ा दी हैं कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ नहीं है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट पर गांधी परिवार



वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, वहीं प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर संशय है।

गांधी परिवार ने खत्म किया यूपी से रिश्ता ?
ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि गांधी परिवार की गढ़ रही अमेठी और रायबरेली सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। खासकर रायबरेली में, क्योंकि 2019 में यही इकलौती सीट थी जिस पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कृयास लग रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती रहें हैं। वो यूपी कांग्रेस की प्रभारी रही हैं और अमेठी और रायबरेली में काफी एक्टिव भी रही हैं लेकिन प्रियंका फलहाल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं।

सीबीएसई की 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाएं कल से

कितने बजे तक विद्यार्थियों को पहुंचना होगा सेंटर में

नई दिल्ली, 15 फरवरी 2024 (ए)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तरफ से कल से 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाएं शुरू की जाने वाली हैं। सीबीएसई कक्षा 12 के छात्र पहले दिन उद्यमिता, कोकबोरोक, पूंजी बाजार संचालन और शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। वहीं, कक्षा 10 के छात्र पहले दिन चित्रकला में गुरुंग, राय, तमांग और शेरेपा की परीक्षा देंगे।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में करीब 35 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। विदेशों में सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल होने की वजह से यह परीक्षा वहाँ भी आयोजित की जाती



है। सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को पेपर लीक के संबंध में फर्जी खबरों और सूचनाओं के प्रति भी सचेत किया है। बोर्ड ने कहा छात्रों को सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी फर्जी खबरों या प्रश्न पत्रों के वीडियो/फोटो पर विश्वास नहीं करना

चाहिए। स्टूडेंट्स को सेंटर पर हॉल टिकट और अपने स्कूल का आईकार्ड लेकर जाना होगा। परीक्षाएं सुबह 10.30 बजे से शुरू होंगी और स्टूडेंट्स को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 45 मिनट पहले सुबह 9:45 बजे तक केंद्र पर पहुंचना होगा।

सरस्वती देवी की

आपत्तिजनक प्रतिमा पर बवाल

अगरतला, 15 फरवरी 2024 (ए)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने वसंतपंचमी के अवसर पर एक सरकारी कॉलेज परिसर में देवी सरस्वती की प्रतिमा को अभद्रता से प्रदर्शित करने



का विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संस्कृति और धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है। उन्होंने संस्थान के प्रशासन पर प्रतिमा को तुरंत एक साड़ी में लपेटने का दबाव डाला। त्रिपुरा में एबीवीपी के संयुक्त सचिव दिवाकर आचार्य जी ने कहा कि संगठन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे पहलुओं का कड़ा विरोध करता है।

कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संस्कृति और धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है। उन्होंने संस्थान के प्रशासन पर प्रतिमा को तुरंत एक साड़ी में लपेटने का दबाव डाला। त्रिपुरा में एबीवीपी के संयुक्त सचिव दिवाकर आचार्य जी ने कहा कि संगठन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे पहलुओं का कड़ा विरोध करता है।

इंडिया गठबंधन को एक और झटका



फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान

नई दिल्ली, 15 फरवरी 2024 (ए)। लोकसभा चुनाव की

तैयारियों के बीच विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नेता फारूक अब्दुल्ला ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किए बिना अपनी योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ेगी। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि जहाँ तक सीट बंटवारे का सवाल है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी ने अचानक इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? उन्होंने एनडीए में जाने की संभावनाओं से इंकार भी नहीं किया।

अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

इस वजह से जीत नहीं पाया शरद पवार खेमा

मुंबई, 15 फरवरी 2024 (ए)। महाराष्ट्र की सियासत के लिए अहम खबर सामने आई है। खबर यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। निर्णय विधायी बहुमत पर आधारित था। ऐसे में अजित गुट को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। नावेंकर ने पवार गुट की तरफ से दाखिल की गई याचिकाएं रद्द करते हुए संख्याबल के हिसाब से अजित पवार के पक्ष



में फैसला सुनाया। नावेंकर ने कहा कि 29 जून तक शरद पवार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं था। उन्होंने कहा कि पार्टी 30 जून 2023 विभाजित हुई थी। नावेंकर ने कहा कि अजित गुट के सभी विधायक योग्य हैं। कोई भी विधायक अयोग्य नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष

राहुल नावेंकर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों ही गुट दावा कर रहे हैं कि वे ही असली एनसीपी हैं। नावेंकर ने कहा, आर्टिकल 21 के मुताबिक, पार्टी की वकिंग कमिटी में 21 सदस्य होते हैं। अजित पवार गुट ने 30 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अजित पवार को 41 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अजित पवार के गुट को विधायक दल का समर्थन प्राप्त है, इसलिए अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है।

डीएमएफ को लेकर केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन

अब मनमाने तरीके से खर्च नहीं कर पाएंगे जिम्मेदार अधिकारी

रायपुर, 15 फरवरी 2024 (ए)। डीएमएफ याने डिस्ट्रिक्ट मिमरल फार्डेशन के तहत मिलने वाले फंड में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए खनिज मंत्रालय ने अब नई गाइडलाइन तैयार की है। देश भर में मिल रही शिकायतों और डीएमएफ के क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों से मिले सुझावों के आधार पर यह दिशा-निर्देश तैयार किया गया है, जिसका पालन होने के बाद खनन क्षेत्र से बाहर डीएमएफ की रकम को खर्च करना मुश्किल होगा। डीएमएफ के कानून के लिए केंद्र

सरकार ने 2015 में खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तैयार की और इसकी गाइडलाइन बनाई। इसके आधार पर ही राज्यों में डीएमएफ का कानून बनाया गया। 2015 से लेकर अब तक डीएमएफ के हो रहे



उपयोग में खामियों को देखते हुए नई गाइडलाइन तैयार की गई है। बदला गया प्रभावित क्षेत्र का दायरा डीएमएफ के तहत किसी भी खदान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित

इलाके का दायरा अब बदल दिया गया है। इसके तहत खदान से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके 'प्रत्यक्ष प्रभावित' माने जायेंगे। वहीं खदान से 25 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके 'अप्रत्यक्ष प्रभावित' माने जायेंगे। अर्थात् डीएमएफ के फंड का इस्तेमाल इन्हीं इलाकों में किया जाना है। उच्च और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को विभाजित कर दिया गया है। इनमें से उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अब 60 की जगह 70 प्रतिशत रकम खर्च करने का प्रावधान बनाया गया है।

संपादकीय

किसान फिर सड़क पर

किसान संगठन दिल्ली चलो' अभियान पर निकल पड़े हैं। इससे 2020 का नजारा फिर से सामने आ खड़ा हुआ है। तब आंदोलन से निपटने के सरकारी उपाय किसानों का हौसला तोड़ने में नाकाम रहे थे। क्या इस बार सरकार सफल होगी? किसान संगठनों की मांगों का ना सिर्फ वर्तमान सत्ताधारी पार्टी, बल्कि आज की पूरी पॉलिटिकल इंकॉर्नमी के साथ तीखा अंतर्विरोध है। इसलिए इसमें कोई हारत की बात नहीं कि चंडीगढ़ में तीन केंद्रीय मंत्रियों की टीम के साथ इन संगठनों की बातचीत नाकाम हो गई। दोनों पक्षों में सहमति सिर्फ तभी बन सकती है, जब उनमें से कोई अपने बुनियादी प्रस्थान बिंदु से हटने को तैयार हो। सरकार तो संभवतः तब तक ऐसा नहीं करेगी, जब तक किसान अपने आंदोलन को इतना बड़ा ना बना दें, जिसका असर सत्ताधारी दल की चुनावी संभावनाओं पर महसूस होने लगे। दूसरी तरफ सरकार की मौजूदा नीतियों से किसान और कृषि अर्थव्यवस्था जिस तरह बदहाल हो रहे हैं, उसके बीच इन संगठनों के पास भी लंबी लड़ाई लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। यही कारण है कि लगभग दो साल के अंतराल के बाद फिर एक बड़े किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई है। कई किसान संगठन मंगलवार को अपने दिल्ली चलो' अभियान पर निकल पड़े हैं। इसके तहत हजारों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली आने की तैयारी में हैं। इस बीच 16 फरवरी को किसान संगठन देश भर में ग्रामीण बंद का आयोजन करेगा। उस रोज ट्रेड यूनियनों भी उनकी इस लड़ाई में शामिल होंगे। दस ट्रेड यूनियनों ने उस दिन हड़ताल पर जाने का एलान किया है। इस बीच दिल्ली प्रशासन ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। दिल्ली की सीमा सीमाओं पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती गई है। सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड, कंटीली तारें और नुकाले उपकरणों को लगा दिया गया है। दिल्ली में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन, जुलूस या यात्रा निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने अलग से ऐसे उपाय किए हैं, जिससे किसानों को दिल्ली पहुंचने के पहले ही रोके दिया जाए। यानी 2020 का नजारा फिर से सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन तब ऐसे उपाय किसानों का हौसला तोड़ने में नाकाम रहे थे। क्या इस बार सरकार सफल होगी?

राजनीतिक पैमाने पर रत्नों का चुनाव

दुनिया का कोई भी पुरस्कार या सम्मान किसी व्यक्ति की महानता के मूल्यांकन का पैमाना नहीं हो सकता है। पिछली सदी के सबसे महान राजनीतिक सामाजिक विचारक और आंदोलनकारी महात्मा गांधी की शान्ति का नोबल पुरस्कार नहीं मिला है। लेकिन इससे गांधी की महानता में रती भर फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही जितने लोगों को नोबल पुरस्कार मिले हैं वे सब हर कसौटी पर महान हैं ऐसा भी नहीं माना जा सकता है। दुनिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, खासकर शान्ति, साहित्य और अर्थशास्त्र का नोबल अवसर भू-राजनीतिक स्थितियों से प्रभावित होता है। अमेरिकी और पश्चिमी दुनिया के राजनीतिक नैटिव के हिसाब से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तभी इस सर्वोच्च पुरस्कार के विरोधाभास कई बार देरान करने वाले होते हैं। महात्मा गांधी को शान्ति का नोबल नहीं मिला, लेकिन जिस व्यक्ति की कूटनीति से दुनिया के कई हिस्सों में हजारों लोग मारे गए उस हनरी किंजिर को शान्ति का नोबल मिला। अमेरिका को एक के बाद एक छह युद्धों में धकेलने वाले बराक ओबामा को भी नोबल मिला और दुनिया में युद्ध नीति के सबसे बड़े जानकार माने गए किंस्टन चर्चिल को शान्ति का तो नहीं लेकिन साहित्य का नोबल मिला। दुनिया में नोबल पुरस्कारों को लेकर जैसी राजनीति होती रही है और पुरस्कार जिस तरह से भू-राजनीतिक स्थितियों से प्रभावित होते रहे हैं उसी तरह भारत रत्न का भी मामला है। भारत के अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों को उनके निधन को एकदम बाद भारत रत्न दिया गया। सोचें, कैसी विडम्बना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एमजी रामचंद्रन के दो साल बाद 1999 में भारत रत्न मिला और सरदार वल्लभ भाई पटेल व मोरारजी

देसाई को राजीव गांधी के साथ 1991 में भारत रत्न दिया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को तो और भी हतजात्र करना पड़ा। उनको 1999 में भारत रत्न मिला तो मदन मोहन मालवीय को 2015 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। भारत रत्न दिए जाने के इस पैटर्न को देख कर समझा जा सकता है कि किस तरह से विचारधारा के आधार पर सरकारों ने भेदभाव किया और भारत रत्नों का चुनाव किया। अब भी इस देश के सबसे मौलिक राजनीतिक-सामाजिक विचारक राममनोहर लोहिया को भारत रत्न नहीं मिला। बाबू जगजीवन राम से लेकर कांशीराम तक अनेक नेता ऐसे हैं, जिनको यह सम्मान नहीं मिला है। लेकिन इससे भारतीय राजनीति और समाज में उनक योगदान कम नहीं हो जाता है। चूंकि भारत रत्न के लिए ऐसी महान विभूतियों के नाम पर विचार नहीं होता है, जिनका निधन आजादी से पहले हो गया था इसलिए विभूतियों की सूची थोड़ी छोटी हो जाती है फिर भी ऐसी अनेक विभूतियां हैं, जो इससे वंचित रह गई हैं। असम में आजादी के बाद ही कांग्रेस की सरकारों ने इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को राजनीति का एक टूल बना दिया था। आखिरी बार जब कांग्रेस की सरकार को भारत रत्न देने का मौका मिला तो उसने 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया था। उस समय सचिन को उम्र 40 साल के करीब थी और वे खेल से रिटायर भी नहीं हुए थे। सोचें, भारत रत्न में खेल की श्रेणी नहीं थी इसलिए पहले की सरकारों ने महान ध्यानचंद या मिल्खा सिंह को इससे सम्मानित नहीं किया था। लेकिन

जब खेल की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया तो कांग्रेस की सरकार को सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी मिले, जिनको भारत रत्न दिया गया। उस समय लोकसभा के साथ ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी थे तो किसी ने कांग्रेस के नेताओं को समझाया होगा कि इससे महाराष्ट्र लगातार चौथी जीत मिल सकती है। सोचें, कैसी विडम्बना है कि भारत रत्न सचिन और तब तक कोल्ड ड्रिंक्स से लेकर इनवर्टर का विज्ञापन कर नहीं होगी? यह एक बहुत खराब परंपरा है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने आजादी के सबसे बड़े नायकों में से एक और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू के समय ही कर दी थी बहरहाल, कांग्रेस ने जिस तरह भारत रत्न का इस्तेमाल किया अब भाजपा की सरकार भी उसी तरह इसका इस्तेमाल कर रही है। नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के शासन में 10 भारत रत्न दिए हैं, जिनमें से आठ राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले हैं। भूपेन

सिंह क्यों वंचित रहेंगे? इनके पांच के अलावा सिर्फ नरेंद्र मोदी ही भारत रत्न से वंचित हैं। बाकी सभी आठ प्रधानमंत्रियों और दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारीलाल नंदा को भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न के बारे में कुछ नियम तय हैं। जैसे एक अघोषित नियम यह है कि इसकी घोषणा आमतौर पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संस्था पर की जाती है। इस साल गणतंत्र दिवस से पहले एक और बाद में पुरस्कारों की घोषणा हुई है। एक नियम यह भी है कि एक साल में तीन से ज्यादा भारत रत्न नहीं दिए जाएंगे लेकिन इस साल पांच भारत रत्न दिए गए हैं। चुनावी साल में पांच लोगों को भारत रत्न देकर अलग अलग जातियों, समुदायों और भौगोलिक क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक समीकरण को साधने का प्रयास साफ दिख रहा है। जिस तरह से पहले राजनीतिक नफा-नुकसान को ध्यान में रख कर अलग अलग समुदायों या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वालों को खुश करने के लिए भारत

रत्न चुने जाते थे वही परंपरा अब भी चल रही है। नरसिंह राव को भारत रत्न दिया गया, जिन्होंने आर्थिक सुधार किए थे लेकिन यह देखने की जरूरत नहीं समझी गई कि वे पहले प्रधानमंत्री थे, जिनके ऊपर सांसदों को रिश्त देकर अपनी सरकार बचाने के आरोप लगे थे। ये आरोप प्रमाणित भी हुए थे। यह अलग बात है कि संसदीय विशेषाधिकार की वजह से रिश्त देने वाले सांसदों और देने वाले सभी बच गए थे चौधरी चरण सिंह महान किसान नेता थे। उनकी ईमानदारी की भी किस्से कहे जाते हैं। लेकिन उनका ही अकल्पनीय उनका सत्ता मोह था। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने

राजनारायण के साथ मिल कर जिस तरह से जोड़ तोड़ किए थे, कई बार पार्टियां बदलीं और उस समय बाबू जगजीवन राम को बदनाम करने के लिए उनके बेटे सुरेश राम की एक महिला के साथ अश्लील तस्वीरों का कॉपी से साथ मिल कर जैसा इस्तेमाल हुआ था वह उनकी राजनीति के उजले पक्ष को नहीं दिखाता है। जिस कांग्रेस के खिलाफ जीवन भर लड़े उसकी मदद से प्रधानमंत्री बनने और अपमानजनक तरीके से हटने के घटनाक्रम से कोई अच्छा राजनीतिक मानक स्थापित नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वैचारिक व राजनीतिक मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया। उनके ऊपर अलग अलग जातियों, समुदायों और भौगोलिक क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक समीकरण को साधने का प्रयास साफ दिख रहा है। जिस तरह से पहले राजनीतिक नफा-नुकसान को ध्यान में रख कर अलग अलग समुदायों या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वालों को खुश करने के लिए भारत



लोकतंत्र में नक्सलवाद और माओवाद गंभीर चुनौती

केन्द्र सरकार लगातार दावे करती रही है कि नक्सलवाद और माओवाद जैसे चरमपंथी संगठनों को प्रभावहीन कर दिया गया है लेकिन छत्तीसगढ़ के वीजापुर जिले में वीते मंगलवार की घटना ने एकबार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि यहां इन संगठनों की जड़ें जमीं हुई हैं। यहां माओवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान तीन सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और 15 अन्य घायल हो गए। सुरक्षाकर्मियों की जवाबी कार्रवाई में 6 माओवादी भी मारे गये। यह मुठभेड़ वीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर स्थित टेकलगुडम गांव के पास उस समय हुई जब कोवरा कमांडो की 201 बटालियन और सीआरपीएफ की 150 बटालियन का संयुक्त दल तलाशी अभियान चला रहा था। लोकतंत्र में नक्सलवाद और माओवाद जैसी हिंसक विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। इसलिए केन्द्र की सरकार माओवाद से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिये प्रभावी कदम उठा रही है। अगर पिछले 10 वर्ष की घटनाओं को देखा जाये तो माओवादी घटनाओं में काफी गिरावट आई है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने दो तरह की रणनीति बनाई है। पहली, माओवादियों के खिलाफ सघन अभियान चलाना और दूसरी, इससे प्रभावित

इलाकों में दूरत गति से विकास करना। अभी पिछले दिनों ही केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश अगले 3 साल में माओवाद और नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होजायेगा। माओवाद और नक्सलवादी आन्दोलन के उभार के कारणों की पड़ताल करें तो यह तथ्य सामने आता है कि कम्युनिस्ट खेमे आदिवासियों के मन में यह भाव स्थापित करने में सफल रहे हैं कि उनका लगातार शोषण हो रहा है। उन्हें उनके जल, जंगल और जमीन से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में उनको इसका प्रतिरोध करना चाहिए। इस बात के आलोक में यह कहा जा सकता है कि जब तक आदिवासियों के मन से यह भाव समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक नक्सल समस्या से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में केवल आर्थिक विकास ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ सांस्कृतिकविकास भी आवश्यक है। नक्सल समस्या का सम्बन्ध आदिवासियों की अस्मिता से भी जुड़ा हुआ है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि लोकतंत्र में उनकी अस्मिता का सम्मान हो रहा है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और आदिवासी समाज के लिए हितकारी है।



काठ की हांडी दोबारा चढ़ाने की कोशिश

भारत सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने 10 साल के राज की कामयाबियों के बारे में बताने के साथ साथ उससे 10 साल पहले के कांग्रेस राज की कमियां बताई हैं। सोचें, 10 साल पहले जिन मुद्दों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा था, जिन मुद्दों को नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार की थीम में रखा था, जिन मुद्दों को लेकर नारे गढ़े थे और पूरे देश में होर्डिंग्स-पोस्टर लगे थे उन्हीं मुद्दों पर फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी है। सरकार को पता था कि जब वह मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल यानी 2004 से 2014 के राजकाज पर श्वेत पत्र लाएंगी तो यह स्वाल उठेगा कि अभी इसकी क्या जरूरत है इसलिए श्वेत पत्र में बताया गया है कि 2014 में चुनाव जीतने के बाद श्वेत पत्र इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि उससे लोगों का मनोबल टूटता और विदेशी निवेशकों में नकारात्मक मैसेज जाता। सोचें, किन्तु लक्ष्य तर्क है। क्या विदेशी निवेशक सरकारी आंकड़ों पर निर्भर रहते हैं? उनके पास वल्यूड बैंक से लेकर आईएमएफ जैसी संस्थाओं के अलावा एसएफडी, फिच, पीइएनसी, मेरिल लिंच जैसी दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, जो रियल टाइम वास्तविक डेटा उपलब्ध कराती हैं और विदेशी निवेशक उसके आधार पर फैसला करते हैं। जहां तक लोगों के मनोबल का स्वाल है तो इंडिया ऑपेंट करण यानी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने मिल कर

भ्रष्टाचार का ऐसा हल्ला बनवाया था कि उसके बारे में जानने के लिए किसी को श्वेत पत्र की जरूरत ही नहीं थी। बाद में भाजपा ने अपने प्रचार से इसे और कोड़ा मुद्दा बना दिया। सरकार को पता है कि भाजपा इस मुद्दे को 10 साल पहले धुना चुकी है। इसलिए उस समय श्वेत पत्र लाने का कोई मतलब नहीं था। लोगों को सब कुछ पता था। उल्टे थोड़े दिन के बाद इन सबकी हकीकत भी खुल गई, जब संचार घोटाले के आरोपी बरी हो गए, कोड़ा घोटाले में किसी नेता को सजा नहीं हुई, मनमोहन सिंह को कोई आंच नहीं आई और महंगाई वैसी ही रही, जैसे पहले थी या उससे बढ़ गई। अब 10 साल बाद श्वेत पत्र लाकर उस समय की यादों को ताजा बनाया जा रहा है। लेकिन यह काठ की हांडी को दोबारा चूल्हे पर चढ़ाने की तरह है, जिसका कोई तर्क अभी समझ में नहीं आता है। जब रामजी आ गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, काशी कॉरिडोर बन गया है, महाकाल लोक का उद्घाटन हो गया है, मां कामध्या और मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है, समान नागरिक संहिता लागू होनी शुरू हो गई है, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, तीन तलाक के खिलाफ कानून बन गया है और केंद्रीय मंत्री खम टोंक कर रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए चुनाव से पहले लागू होने जा रहा है तो फिर ऐसे श्वेत पत्र का क्या मतलब है, जिसकी बारीकी में जाने

पर खुद सरकार की पोल खुलती है? सरकार दावा कर रही है कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय महंगाई की दर बहुत ऊंची थी। इसमें प्रचार से इसे और कोड़ा मुद्दा बना दिया। सरकार को पता है कि भाजपा इस मुद्दे को 10 साल पहले धुना चुकी है। इसलिए उस समय श्वेत पत्र लाने का कोई मतलब नहीं था। लोगों को सब कुछ पता था। उल्टे थोड़े दिन के बाद इन सबकी हकीकत भी खुल गई, जब संचार घोटाले के आरोपी बरी हो गए, कोड़ा घोटाले में किसी नेता को सजा नहीं हुई, मनमोहन सिंह को कोई आंच नहीं आई और महंगाई वैसी ही रही, जैसे पहले थी या उससे बढ़ गई। अब 10 साल बाद श्वेत पत्र लाकर उस समय की यादों को ताजा बनाया जा रहा है। लेकिन यह काठ की हांडी को दोबारा चूल्हे पर चढ़ाने की तरह है, जिसका कोई तर्क अभी समझ में नहीं आता है। जब रामजी आ गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, काशी कॉरिडोर बन गया है, महाकाल लोक का उद्घाटन हो गया है, मां कामध्या और मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है, समान नागरिक संहिता लागू होनी शुरू हो गई है, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, तीन तलाक के खिलाफ कानून बन गया है और केंद्रीय मंत्री खम टोंक कर रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए चुनाव से पहले लागू होने जा रहा है तो फिर ऐसे श्वेत पत्र का क्या मतलब है, जिसकी बारीकी में जाने

तो

वो जब आते हैं, खवाबों में, खयालों में, क्वों, लूट ले जाते हैं, दिल का चैनो अमन, और, हम खो जाते हैं, मय के प्यालों में, वो, जब मिल के बिछुड़ जाते हैं, तो यूँ लगता है, जैसे सूखे हुए फूल, मिलते हैं अब कितानों में, वो, जब मिलते हैं, यादों की मुलाकातों में, तो, यूँ लगता है जैसे, मनमाती कोयल गा, रही हो सावन में।

डॉक्टर जय महानवाल
बिलासपुर हिमाचल प्रदेश

स्त्री और वसंत

वसंत जैसी होती हैं स्त्रियाँ जो कदम रखते ही बीहड़ को भी कर देती हैं उपवन बना देती हैं सूने से मकान को सुंदर घर कोने-कोने से धूल भर जाले साफ करके खिड़कियों पर मर्यादा के पर्दे डाल देती हैं जिनकी पायल की छम छम से बजने लगते हैं घर में शंखनाद एक स्त्री ही है जिसके बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। जिसके तुलसी पूजन से होने लगती हैं चारों दिशाएँ सुभाषित जिसके कदमों की आहट से खिलने लगते हैं गृह आँगन की क्यारी में फूल जिसके केशों की घटाओं में सिमट जाते हैं दोनों जहाँ जिसके होने मात्र से घर का सुनावन भर जाता है मधुर कलरव से जिसके हाथों का भात खाकर मिलती है क्षुधा पीड़ित उदर को तृप्ति जिसके दुग्ध रूपी अमृत का पान करके शैशव पाता है नवजीवन हौं ऋतुराज जैसी ही होती हैं स्त्रियाँ जिनके आँचल में आकर ठहर जाती है चिरकालिक बहार और प्रत्येक ऋतु लगती है मधुमास जैसी।

छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया

छत्तीसगढ़ के बोली भाखा, सब के मन ला भाथे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हमर देश मा कहथे। छत्तीसगढ़ के संस्कृति, हमर अलग पहिचान है। हमन छत्तीसगढ़िया जी, हम ला गब गुमान है। इहाँ के सुघर गुरतुर बानी हदय ला जुड़थे...। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हमर देश मा कहथे। छत्तीसगढ़ ला कहथे संगी, धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ महतारी हमर लक्ष्मी दाई के कोरा। अरपा पैरी अउ महानदी के धार हू बोहथे...। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हमर देश मा कहथे। ताँवा लोहा जस्ता पीतल, खनिज के भंडार है। उपजाऊ है इहाँ के माटी, उन्नत खेती-खार है। चटनी संग मा बोरे बासी अब्बड़ के मोठाथे...। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हमर देश मा कहथे। बड़े बिहिनिया चले किसनहा, करथे खेती किसानी। धरती दाई के सेवक करत, चलत हावय जीनगानी। धान गहू चना राहेर मसूर के फसल लहलहथे...। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हमर देश मा कहथे।

जब राज्य समृद्ध होते, तो संघ भी समृद्ध

वर्ष 2024 भारत के लिए महत्वपूर्ण है - देश आम चुनाव की ओर अग्रसर है। नई सरकार के कार्यकाल 2024-29 के दौरान, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी सीमा को पार कर जाएगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दरअसल, भारत 7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के करीब पहुंच जाएगा। यह वर्ष, जो 2000 और 2017 के बीच लगभग आधा है, भविष्य के प्रक्षेप पथ के बारे में जायजा लेने के लिए एक सुविधाजनक बिंदु है। जब तक नई सरकार का कार्यकाल समाप्त होगा, तब तक दुनिया सतत विकास लक्ष्यों या एसडीजी की समय सीमा के करीब पहुंच जाएगा। अधिकांश देश उन लक्ष्यों से फिसल गए हैं, हालांकि भारत दूसरों की तुलना में कम फिसला है। विकास का संबंध सामाजिक क्षेत्र के संकेतकों में सुधार से है। मध्यम अवधि में, भारत किस विकास पथ पर है? ए-5-5-6 प्रतियोगिता; बी-6.5-7 प्रतियोगिता; या सी) 7.5-8 प्रतियोगिता, बी और सी के बीच अंतर तेजी से बढ़ता है। किसी भी प्रक्षेपण के लिए मान्यताओं के

एक सेट की आवश्यकता होती है - वास्तविक विकास दर, मुद्रास्फीति, जनसंख्या वृद्धि की दर, कुल कारक उत्पादकता में वृद्धि और रफ्तार-डॉलर विनिमय दर। उदाहरण के लिए, कोविड तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग मिलने की संभावना है। इस दर पर, भारत में हर 2 साल में 0.75 ट्रिलियन डॉलर जुड़ने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि भारत 2047 तक 20

1.7 अरब की अनुमानित आबादी के साथ, कोई यह अनुमान लगा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय 12,000 डॉलर से कम होगी। इसके विपरीत, मार्च 2023 में अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा किया गया एक अध्ययन है, जिसमें कहा गया है - सबसे पसंदीदा परिदृश्य में, भारत 2027-28 में बाजार विनिमय दर के मामले में 5, 10 और 20 ट्रिलियन की संभावना है। क्रमशः 2035-36 और 2044-45... बाजार विनिमय दर के संदर्भ में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2044-45 तक 13,000 डॉलर को पार करने की उम्मीद है, जो इसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में ला देगी... सबसे पसंदीदा परिदृश्य के अनुसार, भारत की वास्तविक जीडीपी 6-6.4 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है 2022-23 से 2047-48 की अवधि में, हालांकि मध्यम दशकीय वृद्धि प्रोक्षल के साथ... ट्रिलियन के संदर्भ में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद पूर्वानुमानित अवधि (2022-23 से 2047-48) के दौरान लगभग 8.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

श्याम सुंदर साहू
राजिम गरियाबंद छत्तीसगढ़

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

प्रति चौधरी मनोरमा बुलंदशहर उत्तरप्रदेश

राजकुमार निषाद राज बिरोदा धमथा दुर्ग छत्तीसगढ़

बीमा कंपनी को देने होंगे 1 करोड़ रुपए, न्यायालय

स्थायी लोक अदालत ने विधवा के पक्ष में सुनाया फैसला

- संवाददाता -

अम्बिकापुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

पति की मौत के बाद एक महिला बीमा की राशि पाने छई साल से दर-दर भटक रही थी। बीमा कंपनी ने यह कहकर बीमा की राशि देने से इनकार कर दिया था कि बीमाधारक की मौत शराब सेवन से हुई बीमारी के कारण हुई थी। गौरतलब है कि महिला के पति ने 30 नवंबर 2018 को आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ का बीमा कराया था। वर्ष 2021 में उसकी मौत हो गई थी। बीमाधारक की पत्नी ने बीमा राशि के लिए कंपनी को आवेदन किया था। पीड़िता ने बीमा राशि के लिए बीमा कंपनी के केन्द्रीय कार्यालय महाराष्ट्र व बीमा लोकपाल भोपाल तक का दरवाजा खटखटाया था। इसके बावजूद उसे राशि नहीं मिली। इससे परेशान महिला ने मार्च 2023 में न्यायालय स्थायी लोक अदालत अम्बिकापुर में बीमा कंपनी के खिलाफ परिवार दायर किया था। अदालत ने 11 माह



लोक अदालत

बाद बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए पीड़िता को एक माह के भीतर बीमे की राशि 1 करोड़ रुपए व मार्च 2023 से अब तक 7 प्रतिशत ब्याज की दर से बीमा की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। भुगतान नहीं करने पर ब्याज की दर 9 प्रतिशत कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि शहर के दरौपार निवासी गणेश करण ने 30 नवंबर 2018 को आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपना 1 करोड़ का बीमा कराया था। उसने बीमा के दस्तावेज में पत्नी, पिता व मां को

नामनी बनाया था। 11 नवंबर 2021 को किसी बीमारी से उसकी मौत हो गई। गणेश की मौत से पूर्व उसके पिता की भी मौत हो गई थी। ऐसे में नामनी ने केवल पत्नी व मां ही बची थी। इधर पत्नी सविता करण ने बीमा राशि के लिए आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शाखा अम्बिकापुर में दस्तावेज जमा किए। इसके कुछ दिन बाद कंपनी ने बीमा की राशि देने से इनकार कर दिया। बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि बीमाधारक की मौत शराब सेवन से हुई बीमारी के कारण हुई है। इसलिए बीमा राशि का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता

है। जबकि डॉक्टर की रिपोर्ट में बीमाधारक की मौत का कारण शराब सेवन से नहीं बताया गया था। इधर बीमाधारक की पत्नी बीमा राशि के लिए बीमा कंपनी के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे रुपए का भुगतान नहीं किया गया।

केन्द्रीय कार्यालय व बीमा लोकपाल तक गुहार

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शाखा अम्बिकापुर द्वारा बीमा क्लेम रिजेक्ट किए जाने के बाद पीड़िता ने बीमा कंपनी के केन्द्रीय कार्यालय महाराष्ट्र व बीमा लोकपाल भोपाल में भी आवेदन दिया, लेकिन वहां भी उसे मायूसी मिली। बीमा लोकपाल ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि

7 प्रतिशत ब्याज भी देने होंगे

न्यायालय स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) अम्बिकापुर की अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता ने बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर पीड़िता को 1 करोड़ रुपए व मार्च 2023 से 1 करोड़ रुपए का 7 प्रतिशत ब्याज देने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसी समय में 20 हजार रुपए मानसिक क्षति व 5 हजार रुपए वाद व्यय भी देने कहा है। 30 दिन में ये राशि नहीं देने पर ब्याज की राशि 9 प्रतिशत बढ़ाए जाने की बात कही गई है।

कार्मेल स्कूल की छात्रा अर्चिषा के आत्महत्या के बाद जागा प्रशासन, बनी निरीक्षण समिति

- संवाददाता -

अम्बिकापुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

नगर के कार्मेल स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा छठवीं की छात्रा अर्चिषा सिन्हा के आत्महत्या के बाद प्रशासन जागा है। सरगुजा जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान पर प्राप्त विद्यालयों में समय-समय पर निरीक्षण कर आवश्यकता नुरूप अ व र य क सु धार ा र्म क सुझाव दिए जाने हेतु निरीक्षण समिति का गठन कलेक्टर विलास भोस्कर संदीपन ने किया है।



निरीक्षण समिति का अध्यक्ष सरगुजा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार को बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी डा संजय गुहे समिति के सचिव बनाए गए हैं। अम्बिकापुर के एसडीएम फारोश सिन्हा, महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी जेआर प्रधान, उच्च शिक्षा विभाग के अपर संचालक व राजीव गांधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डा रिजवानउल्ला, एक समाचार पत्र से अनंगपाल दीक्षित, अधिवक्ता अभिषेक शर्मा, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश एक्का, अंबेडकर कालेज के मनोचिकित्सक डा संदीप टो, डा ममता लकड़ा, सहायक परियोजना अधिकारी जिला शिक्षा विभाग रविशंकर पांडेय, सामाजिक क्षेत्र से सपना व संस्था के प्राचार्य को सदस्य बनाया गया है।

बाइक से नर्सरी में ले जाकर किया बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार

सरगुजा विद्युत ठेकेदार संघ के अध्यक्ष बने विजय सोनी

- संवाददाता -

अम्बिकापुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।



- संवाददाता -
अम्बिकापुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

घर छोड़ देने की बात कह कर युवक ने बाइक में बैठकर युवती को नर्सरी के पास लेजाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।

मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। पुलिस के अनुसार एक युवती किसी काम से सोसायटी गई थी। वहीं पर उसे जान पहचान का युवक

राजू बेक मिला। राजू युवती को घर तक छोड़ देने की बात कह कर उसे बाइक में बैठाकर नर्सरी की ओर लेजाकर उसके साथ बलात्कार किया।

पीड़िता ने किसी तरह घर पहुंची और मामले की जानकारी परिजन को दी। परिजन के साथ वह थाना पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी राजू बेक पिता मोहर साय उम्र 35 वर्ष निवासी राधापुर तेंदुपारा को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। कार्रवाई में थाना सीतापुर से महिला आरक्षक लक्ष्मिनिा टोपों, आरक्षक पंकज देवानन, संजय एक्का, अशोक खेस सैनिक रमेश विश्वकर्मा शामिल रहे।

सरगुजा विद्युत ठेकेदार संघ के विजय सोनी अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। गुरुवार को अम्बिकापुर के होटल पंचानन में जिले भर के बिजली ठेकेदारों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से विजय सोनी को सरगुजा विद्युत ठेकेदार संघ का अध्यक्ष मनोनीत कर लिया गया। उपाध्यक्ष पद पर अम्बिकापुर के ही बिजली ठेकेदार अभयदीप सिंह का मनोनयन किया गया है। विजय सोनी सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों में हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं। अम्बिकापुर नगर निगम के पूर्व पार्षद तथा एमआईसी के पूर्व सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी में बतौर ठेकेदार कार्य करने का उन्हें लंबा अनुभव है। उत्तर छत्तीसगढ़ के शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी की मंशा अनुरूप बिजली विस्तार तथा घर-घर



बिजली पहुंचाने का काम किया

सरगुजा के प्रथम पंक्ति के बिजली ठेकेदार विजय सोनी को सरगुजा की बिजली व्यवस्था की बारीक जानकारी है। दूरस्थ ग्राम से लेकर नगरीय क्षेत्र में बिजली के माध्यम से सुदूरकरण का भी उन्हें लंबा अनुभव है।

सरगुजा अंचल में बिजली सुविधा विस्तार में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कार्यकारिणी में उनके साथ शामिल अम्बिकापुर के अभयदीप सिंह भी पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी में कार्य कर रहे हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय सोनी ने

कहा कि बिजली ठेकेदारों की समस्याओं के निराकरण के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से समन्वय बनाकर सरकार की मंशा के अनुरूप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने संघ की ओर से पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा

मणिपुर स्कूल में मधुमक्खियों ने बच्चों पर किया हमला, 14 जखमी

स्कूल में वार्षिकोत्सव का चल रहा था कार्यक्रम

- संवाददाता -
अम्बिकापुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

शहर के मणिपुर प्राथमिक शाला में गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इससे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। वहीं मधुमक्खियों के हमले में लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चे जखमी हो गए। स्कूल के शिक्षकों द्वारा तत्काल बच्चों को ऑटो से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। सभी बच्चों की हालत सामान्य है। घटना के दौरान स्कूल में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। इस लिए स्कूल परिसर में ज्यादा बच्चे मौजूद थे।



प्राथमिक शाला मणिपुर में शुक्रवार को वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम स्कूल परिसर में

चल रहा था। इस दौरान काफी संख्या में स्कूल के बच्चे, शिक्षक व अभिभावक मौजूद थे। लगभग दो बजे अचानक

मधुमक्खियों का एक झुंड ने स्कूल परिसर में मौजूद बच्चों पर हमला कर दिया। इससे स्कूल परिसर में अफरा-

फतरी मच गई। मधुमक्खियों के हमले में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग जखमी हो गए। वहीं दो अन्य महिलाएं भी जखमी हुई हैं। मधुमक्खियों के शांत होने पर स्कूल के शिक्षक व अन्य स्टाफ द्वारा सभी बच्चों को इलाज के लिए तत्काल ऑटो से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। स्थिति सामान्य बताई गई है। मधुमक्खियों के हमले में 12 छात्र-छात्राएं सहित दो युवतियां जखमी हो गई हैं। जिसमें सकीना परवीन (18), सहनूर परवीन (19), रोशनी दास (14), राजेन्द्र राजवाड़े (8), सपना (8), रुद्र (9), अंश (9), सुनील (9), कल्पना (8), अंकुश (14), रौनक (9), सुनीता यादव (12), सत्यम राजवाड़े (8), प्रिंस राजवाड़े (9) जखमी हुए हैं।

दो दिवसीय शिविर में 130 लोगों ने लर्निंग लाइसेंस के लिए कराया पंजीयन

- संवाददाता -

अम्बिकापुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दो दिवसीय लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन पीजी कॉलेज ग्राउंड में किया गया था। शिविर में 130 लोगों ने लर्निंग लाइसेंस के लिए अपना पंजीयन कराया है।

जिले में सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। इस दौरान सरगुजा पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आमनागरिकों की सुविधा के लिए सरगुजा पुलिस एवं परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को दो दिवसीय लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन पीजी कॉलेज ग्राउंड में किया गया। शिविर के पहले दिन 30 व्यक्तियों द्वारा लर्निंग लाइसेंस के लिए पंजीयन कराया गया। वहीं शिविर के दूसरे दिन शुक्रवार को 100 लोगों ने पंजीयन कराया है। दो दिवसीय शिविर में कुल 130 लोगों ने लर्निंग लाइसेंस के लिए पंजीयन कराया है।



महिला के घर में घुसकर किया छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

- संवाददाता -

अम्बिकापुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

रात में महिला के घर में घुसकर युवक द्वारा छेड़छाड़ किया गया था। इस मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एक महिला 11 फरवरी की रात को अपने बच्चों के साथ घर में थी। तभी जानपहचान का ही एक युवक महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता द्वारा हल्ला करने पर परिजन जग गए। इसे देख आरोपी वहां से फरार हो गया। वहीं पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट धौपुर थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रामप्रसाद पिता नैहर साय उम्र 24 वर्ष निवासी बिल्हमा दरौपारा थाना धौपुर को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।

पुलिस ने छह भैंसों के साथ दो तस्करो को पकड़ा, अन्य दो की तलाश जारी

- संवाददाता -

प्रतापपुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

बुधवार की शाम प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बैकोना से दो लोग छह नग भैंसों को पैदल हकते हुए बलरामपुर जिले की ओर की ओर ले जा रहे थे। इस दौरान उन्हें वहां के ग्रामीणों ने भैंसों के संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के कहने पर वे भैंसों को बलरामपुर जिले के मानिकपुरी गांव तक छोड़ने जा रहे हैं। जब ग्रामीणों ने पूछा कि यह भैंसे किसकी हैं तो वे दोनों गोल-मोल जवाब देने लगे। जिस पर ग्रामीणों को संदेह हुआ तो



उन्होंने उन दोनों को भैंसों सहित रोक्ते हुए इसकी सूचना प्रतापपुर के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को दी। सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता प्रतापपुर पुलिस के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे तो वहां भैंसों के साथ दो लोग खड़े नजर आए। दोनों लोगों से भैंसों से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा गया जिस पर वे कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। जिसके बाद पुलिस दोनों को भैंसो सहित पकड़कर प्रतापपुर थाने ले आई। जहां पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि वे बलरामपुर जिले की ओर ले जा रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए लोगों द्वारा बताए गए अन्य दोनों की भी तलाश शुरू कर दी है।

लखनपुर विकासखंड के अंतर्गत स्थित एसईसीएल का अमेरा खुली खदान में कोयला उत्खनन होने के साथ ही खदान सुर्खियों में है...

- मनोज कुमार -

लखनपुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

अमेरा खुली खदान में एसईसीएल प्रबंधन की लापरवाहियों के कारण स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा कोयला चोरी का मामला हो या भूमि अधिकरण या ग्रामीणों को विस्थापित करने का मामला हो या फिर एसईसीएल प्रबंधन द्वारा रोड सेल कोयला ट्रको से परिवहन में अवैध वसूली का मामला या लाखों रुपए का प्रतिदिन कोयला चोरी रोकने में बेवश और लाचार दिखती है एसईसीएल प्रबंधन।

अमेरा खुली खदान में विगत एक महीना से रोड सेल कोयला परिवहन के नाम से एसईसीएल प्रबंधन और कोयला लोड करने वाले लिफ्टर के माध्यम से प्रति ट्रक लगभग 3 हजार रुपये की अवैध वसूली कराई जा रही है।

जिसमें मुख्य रूप से एसईसीएल प्रबंधक खदान खर्च के नाम पर दो हजार रुपए ट्रकों के भाड़ा में से कटौती की जाती है वहीं ट्रकों



में कोयला लोड करने वाले लिफ्टर के द्वारा पांच सौ रुपए प्रति ट्रक से अवैध वसूली की जाती है और वहीं प्रति ट्रकों को काटा घर में कोयला तैल करने के नाम से 250 रुपये प्रति ट्रक अवैध वसूली किया जाता है। सभी अवैध वसूली को जोड़ने पर तीन हजार रुपए



प्रति ट्रक से अवैध वसूली किया जाने का आरोप लगाया है।

प्रति दिन 40 से 50 ट्रक से लाखों रुपये अवैध वसूली करने का आया मामला

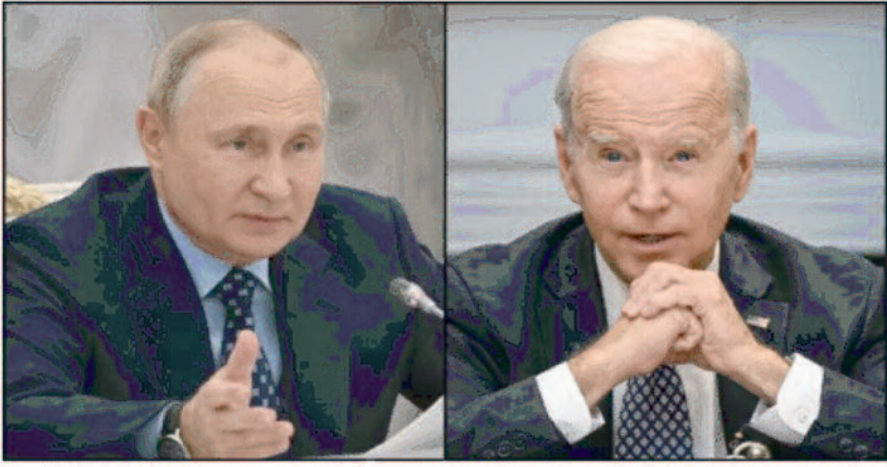
अमेरा खुली खदान में माह जनवरी से रोड सेल का कार्य प्रारम्भ किया गया है

जिसमें ट्रक के माध्यम से कोयला परिवहन किया जा रहा है।

कई कंपनियों के द्वारा एसईसीएल के अमेरा खुली खदान की कोयला की नीलामी के माध्यम से कोयला लिया गया कोयला परिवहन का कार्य जनवरी माह से प्रारम्भ हो चुका है। ट्रक चालकों एवं ट्रक मालिकों के ऊपर एसईसीएल प्रबंधक द्वारा बनाया जाता है दबाव अवैध वसूली के सम्बन्ध में बोलने

पर ट्रक को कर दिया जायगा ब्लेक लिस्टेड। जब पत्रकारों के द्वारा अमेरा खुली खदान में ट्रक चालकों से चल रहे अवैध वसूली के गोरख धंधा के सम्बन्ध में पूछे जाने पर ट्रक चालकों द्वारा बताया गया कि कोयला लोड करने के नाम से लिफ्टरों के द्वारा पांच सौ रुपए लिया जाता है और अमेरा खदान में स्थित काटा घर में 250 रुपये लिया जाता है वहीं ट्रक में तिरपाल लगाने के नाम से भी 250 रुपये लिया जाता है और खदान खर्च के नाम से 2 हजार रुपये भी लिया जाता है इस सभी अवैध वसूली को जोड़ा जाय तो का प्रति काटा घर में 5 हजार रुपये एसईसीएल प्रबंधन और कोयला ठेकेदार के मिलीभगत से लिया जाता है। उक्त जानकारी ट्रक चालकों के द्वारा बताई गई अवैध वसूली की पूरी घटना को बताने के उपरान्त उनके मालिकों को एसईसीएल प्रबंधन द्वारा ट्रकों को ब्लेक लिस्ट करने की भी धमकी एसईसीएल प्रबंधन से आने लगी और ट्रक मालिक और चालकों के द्वारा दिए गए बयान को वापस लेने का बनाया जा रहा है दबाव।

अमेरिकी चुनाव से पहले पुतिन ने की बाइडन की तारीफ, बताया ट्रंप से ज्यादा अनुभवी राजनेता



मॉस्को, 15 फरवरी 2024। अमेरिका में आम चुनाव से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडन की तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने बाइडन को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अनुभवी बताया।

लेकिन हम ऐसे किसी भी अमेरिकी नेता के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, जिस पर अमेरिकी लोग भरोसा करते हैं। पुतिन की ओर से यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले आई है। इन चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी के बाइडन के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा कर सकती है। चुनाव से पहले दोनों सियासी दल यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं।

यूक्रेन की मदद को लेकर आमना-सामना

ट्रंप ने हाल ही में अपने बयानों में कीव के लिए अमेरिकी वित्तपोषण (फंडिंग) पर सवाल उठाया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप नाटो के आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं तो नाटो के जो सदस्य देश

सेना व्यवसाय के बजाए रक्षा पर दे ध्यान, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा आश्वासन



इस्लामाबाद, 15 फरवरी 2024। सेना के राजनीतिक और व्यवसायिक हस्तक्षेप को लेकर पाकिस्तान स्थित सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आलोचना की है। एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आश्वासन मांगा कि सेना रक्षा के अलावा किसी अन्य व्यवसायों पर फोकस नहीं करेगा। गौरतलब है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सैन्य भूमि के इस्तेमाल की जांच करने वाले एक मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश

था। बुधवार को न्यायाधीश ईसा ने खेद व्यक्त किया कि सेना ने सैन्य भूमि पर विवाह हॉल स्थापित किए हैं।

सरकारी संस्थाएं अपनी हद में रहे, सरकार को सुनिश्चित

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ईसा ने अर्दानी जनरल मंसूर उस्मान से कहा कि प्रत्येक सरकारी संस्थान को अपने अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। जज ने कहा कि क्या हमें यह आश्वासन मिल सकता है। सुनवाई के दौरान अर्दानी जनरल ने न्यायाधीश की बातों पर हामी भरी। सुनवाई के दौरान इबैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के वकील ने अदालत को बताया कि जिस इमारत से विवाद हुआ वह बोर्ड की थी क्योंकि जिस व्यक्ति को जमीन आवंटित की गई थी, उसने इसे फर्जी कागजात पर बेच दिया, जिसके बाद पांच मंजिला इमारत बनाई।

सेना रक्षा पर ध्यान दें, न कि व्यवस्थाएं पर- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि देश की सभी संस्थानों को सिर्फ अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, उन्हें सीमाओं के भीतर ही रहना चाहिए। गौरतलब है कि 2021 में यह मामला पर सुनवाई शुरू हुई थी। कराची में छवनी बोर्ड की भूमि का अवैध इस्तेमाल करके वाणिज्यिक लाभ में प्रयोग किया गया

आग की चपेट में आए ग्रामीण की उपचार दौरान मौत

अम्बिकापुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)। आग की चपेट में आए जशपुर जिला के दौनापाट निवासी परसु राम 55 वर्ष की उपचार के दौरान गुरुवार की सुबह मौत हो गई। मृतक आठ फरवरी की शाम को घर के बाहर आग ताप रहा था। कपड़े में आग पकड़ने के बाद अग्नि विभाग आया। चीख-पुकार सुनकर स्वजन पहुंचे और आग बुझाए। अग्नि विभाग को जशपुर जिला अस्पताल से रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर में भर्ती कराया गया था, यहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल से मिली सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

कलेक्टर के निर्देश पर पीवीटीजी बाहुल्य ग्राम खरानगर में मेडिकल टीम ने किया विशेष कैंप

145 हिताग्रहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवाइयों का मिला लाभ

अम्बिकापुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)। गत दिवस बुधवार को उदयपुर दौर पर पहुंचे कलेक्टर विलास भोस्कर ने पीवीटीजी बाहुल्य ग्राम खरानगर में स्वास्थ्य कैंप करने के निर्देश दिए थे जिसके परिपालन में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के टीम के द्वारा विकासखण्ड

उदयपुर के ग्राम खरानगर में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लोगों हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम सितकालो, मतरिंगा एवं खरानगर के लाभार्थी शामिल हुए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के खंड चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त शिविर में कुल 145 लाभार्थी उपस्थित हुए जिनका



शत-प्रतिशत सिकलिन जांच किया गया। 3 गर्भवती महिलाओं की एएनसी यानी प्रसव पूर्व जांच की गई। इसी तरह की गई। इसी दौरान 5 हिताग्रहियों का आयुष्मान कार्ड भी मौके पर ही बनाया

गया। 3 मधुमेह, 2 उच्च रक्त चाप वाले मरीजों की पहचान हुई। सामान्य सर्दी-खासी, अन्य मौसमी बीमारियों से ग्रसित हिताग्रहियों को उचित परामर्श एवं दवाइयों उपलब्ध कराया गया। कैंप में जनरल सर्जन डॉ. कान्ता सिंह, ग्रामीण चिकित्सा सहायक श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिहरलाल, चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनन्द जायसवाल, ए.एन.एम. श्रीमत् चन्द्रावती मरावी, ए.एन.एम. श्रीमती राखी हरदाहा, एवं अन्य स्वास्थ्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

युवा खेती से जुड़ेगा तभी देश खुशहाल होगा:चुरेंद्र

- रेडियो किसान दिवस पर सरगंवा में जुटे कृषि वैज्ञानिक व किसान
- सरगुजा संभाग आयुक्त जीआर चुरेंद्र, भाजपा नेता अतिकेश केसरी ने किया प्रोत्साहित



काम करते हैं तो आप हम यह काम क्यों नहीं करते। आज हर व्यक्ति में कर्मठता की जरूरत है जिसमें कर्मठता होगी वह आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जागरूक रहने, प्रगतिशील रहने से ही हर क्षेत्र में विकास होगा। उन्होंने कहा कि खेती को बढ़ावा देने भारत सरकार कई कार्य योजना संचालित कर रहा है। एक समय था जब किसान कर्ज के तले मर जाता था पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। आधुनिक खेती ने किसानों को खुशहाल बनाया है। सरकारी योजनाओं ने किसानों को मदद की है। उन्होंने कहा कि अब जैविक खेती की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती से न सिर्फ मिट्टी स्वस्थ होगी बल्कि उससे उपजने वाला अनाज भी स्वस्थ और गुणवत्तायुक्त होगा। हम भौतिकवादी जीवन में प्राकृतिक चीजों को भूल चुके हैं। हमें जंगल बचाने होंगे, हमें प्राकृतिक खेती के तरीके को फिर से वापस लाना होगा। एक गाय पाल कर हम एक एकड़ खेत को जैविक उर्वरता से भरपूर बना सकते हैं। उन्होंने सलाह दी की खंड जमीन को छोटी छोटी ब्यारी बनाकर खेती करें। समूह में खेती करें। साग सब्जी व हर तरह की खेती करने से किसान मालामाल होगा। उन्होंने आकाशवाणी अम्बिकापुर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की प्रशंसा की।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के निदेशक भाजपा जिला उपाध्यक्ष अतिकेश केसरी ने कहा कि रेडियो सबसे पुराना इंटरनेट मीडिया है। आकाशवाणी केंद्र द्वारा उन्नत कृषि की नई तकनीक की जानकारी रेडियो से ही मिलती है। प्रधानमंत्री ने लाल किला से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने कहा है। हमें इस दिशा में काम करने की जरूरत है। हम हाइब्रिड अनाज प्रति एकड़ 35 क्विंटल पैदा कर रहे हैं पर हमें इस

कृषि कार्य में आर्थिक लाभ दिलाने के नाम पर किसानों से ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार



अम्बिकापुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)। जैविक खेती एवं कृषि कार्य में आर्थिक लाभ दिलाने के नाम पर सरगुजा संभाग के

कई किसानों से ठगी की गई थी। इस मामले में दो आरोपी को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। पुलिस के अनुसार बलरामपुर जिले के दो किसानों ने थाना गांधीनगर में 28 अक्टूबर 23 को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि सरगुजा मंच प्रायवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जैविक खेती एवं कृषि कार्य, बोर खनन व मुर्गी पालन के लिए आर्थिक सहयोग के नाम पर कई किसानों से लाखों रुपए ठगी की गई है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कंपनी के संचालिका लता खुटे सहित अन्य पर अपराध दर्ज किया था। इस जगत में पुलिस ने राजराम जगत पिता हरि प्रसाद जगत (45) निवासी गोर्गा, जजावल थाना चन्दौरा जिला सरगुजा व जीसू तिकी पिता सुखलाल तिकी (32) निवासी बोदा पोस्ट बिलासपुर थाना बतौली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

मैनपाट महोत्सव स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर:एसपी



अम्बिकापुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)। कलेक्टर विलास भोस्कर और पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने गुरुवार को

मैनपाट महोत्सव स्थल का निरीक्षण किया। रोपाखण जलाशय के नजदीक निर्धारित महोत्सव स्थल में डेम निर्माण, मंच एवं स्थल की साज-सज्जा, साफ-सफाई, हेलीपैड, रंग रोगन आदि का काम चालू है। कलेक्टर श्री भोस्कर ने इस दौरान मुख्य अतिथियों के लिए आवश्यक तैयारियां, मंच पर बैठक व्यवस्था, कार्यक्रम में आमंत्रित कलाकारों का लाइन अप, महोत्सव स्थल पर वीआईपी, मीडिया, अधिकारियों और आम जन की बैठक व्यवस्था, स्टॉल निर्माण, हिताग्रहियों को सामग्री वितरण, पार्किंग की व्यवस्था, रूट चार्ट आदि की जानकारी, बोटिंग प्लांट रोपाखण और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल मेहता प्लांट में सुरक्षा हेतु जरूरी सावधानियों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय कर कार्यक्रम को सफल बनाना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस और राजस्व की टीम को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि रूट चार्ट और पार्किंग व्यवस्था को सहज और सुलभ बनाने के लिए जगह जगह आवश्यक साइन बोर्ड जरूर लगाए जायें। जिससे लोगों को आवागमन में किसी तरह की समस्या ना हो और प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत नूतन कंवर, नगर निगम आयुक्त प्रकाश सिंह रावत सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

कोल माइंस स्टॉक में घुसकर डकैती करने के मामले में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही

- थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही कर मामले में 01 विधि से संघर्षरत बालक सहित कुल 04 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
- आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा, कोयला, ताम्बे का तार किया गया बरामद
- मामले के शेष आरोपियों का पता तलाश कर शीघ्र किया जायगा गिरफ्तार

प्रकरण है कि प्रार्थी फेकू राम आत्मज पद्म शाह उम्र 51 वर्ष साकिन कुंजपुर थाना जयनगर जिला सरगुजा द्वारा अपने मैनेजर, उप क्षेत्रिय प्रबंधक सहित अन्य स्टाफ को सूचना दिया गया कि घटना दिनांक 14/02/24 को अमेरा कोयला खदान के कोयला स्टॉक में 11 से 12 व्यक्तियों द्वारा लाठी डंडा लेकर अंदर आकर सुरक्षा गार्ड को जान से मारने की धमकी देते हुए ताम्बे का तार, कोयला एवं अन्य सामान की डकैती कारित किये हैं, सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल घटनास्थल पहुंचकर मामले में शामिल 01 विधि से संघर्षरत बालक सहित कुल 04 आरोपियों को मौके से पकड़ गया है। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) आर्यन राजवाड़े आत्मज भुनेश्वर राम उम्र 19 वर्ष ग्राम पुहुयुटा



लखनपुर (02) सुरेंद्र कुमार आत्मज रतन राम उम्र 18 वर्ष 03 माह ग्राम पुहुयुटा लखनपुर (03) लवकेश कुमार सोनवानी आत्मज परशु राम सोनवानी उम्र 18 वर्ष साकिन 05 माह ग्राम सिरकोतंगा

लखनपुर का होना बताया, विधि से संघर्षरत बालक एवं अन्य आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अमेरा कोयला खदान में 11-12 व्यक्तियों द्वारा मिलकर लाठी डंडा लेकर कोयला स्टॉक में घुसकर ताम्बे का तार, कोयला एवं अन्य सामान की डकैती कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है, विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर बाल संप्रेशण गृह भेजा जाता है, मामले के शेष फरार आरोपियों के सम्बन्ध में पता तलाश किया जा रहा है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना लखनपुर से प्रधान आरक्षक बलभद्र ठाकुर, रवि सिंह, आरक्षक मुनेश्वर पैकरा, डॉक्टर सिंह सिदार, राकेश चतुरे शांति रहे।

क्या कांग्रेस के गढ़ में फूट की हुई शुरुआत, रनई जमींदार परिवार के विकास ने आरआरएस के रास्ते भाजपा में प्रवेश का चुना मार्ग ?



क्या रनई टूट सकती है राजनीतिक परंपरा ?

ग्राम का जमींदार परिवार आरंभ से ही कांग्रेस पार्टी विचारधारा से जुड़ा रहा और जिसके कारण ग्राम के सभी लोग भी कांग्रेस पार्टी के लिए ही समर्पित बने रहे जिसकी बानगी तब तब देखने को मिली जब जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए और एकतरफा कांग्रेस पार्टी को ग्राम से बढ़त मिलती रही। लेकिन अब लगता है रनई ग्राम भी आजादी के बाद पहली बार अपनी परम्परा खासकर राजनीतिक परंपरा तोड़ सकती है और अब ग्राम में भाजपा का भी झंडा देखने को मिलेगा जो नजर नहीं आया करता था। रनई जमींदार परिवार के एक सदस्य अब भाजपा की तरफ रुख करते देखे जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रास्ते वह भाजपा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं प्रवेश चाहते हैं यह देखने में आने लगा है। आरएसएस के लोगों से संपर्क वहीं राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापना दिवस 22 जनवरी को जमींदार परिवार के यही सदस्य काफी सक्रिय नजर आए थे वहीं उन्होंने ऐतिहासिक एक कार्यक्रम ग्राम में किया था। 22 जनवरी को ही यह माना जाने लगा था की अब रनई वह रनई नहीं रह गया जहां कांग्रेस या जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था अब यहां भी भाजपा का प्रभाव देखने को मिलेगा जो अब स्पष्ट होने लगा है।

क्या रनई जमींदार परिवार के विकास परिवार से हटकर अलग ही राजनीतिक भविष्य बनाने का सोचा रहे ?

रनई जमींदार परिवार के विकास ने अब परिवार से हटकर अलग ही राजनीतिक भविष्य अपना बनाने का सोचा है ऐसा लगने लगा है। हाल फिलहाल में वह कई बार भाजपा नेताओं से मिलते नजर आ रहे हैं वहीं 26 जनवरी को भी उन्होंने भाजपा नेताओं से मुलाकात की थी जिसे सार्थक बताया गया था। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब रनई ग्राम में जमींदार परिवार का ही कोई सदस्य अलग रास्ते अलग राजनीतिक दल का दामन थामेगा। जमींदार परिवार के विकास को भाजपा की ओर प्रेरित करने का काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग कर रहे हैं और वह प्रभावित भी हैं संघ की विचारधारा से ऐसा बताया जा रहा है। अब प्रारंभिक रणनीति में तो रनई के विकास भाजपा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं आगे उन्हे क्या जिम्मेदारी मिलेगी वहीं वह कितने भाजपा के लिए फायदेमंद होंगे यह आगे के चुनाव परिणामों के बाद स्पष्ट हो सकेगा।

क्या रनई के विकास रनई में भाजपा को दिलाएंगे चुनाव में बढ़त ?

रनई ग्राम का इतिहास रहा है की ग्राम में कांग्रेस को ही बढ़त मिलती आई है और ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब वहां किसी अन्य दल को बढ़त मिली हो। अब जमींदार परिवार के विकास ने भाजपा की तरफ रुख किया है, यदि वह निश्चित रूप से भाजपा से जुड़ जाते हैं तो क्या आने वाले समय में ग्राम में भाजपा कांग्रेस से आगे निकलकर बढ़त बनाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी की विकास भाजपा को अपने ही ग्राम से कितनी बढ़त दिला पाते हैं यदि उनका भाजपा प्रवेश होता है।

क्या विकास बदलेंगे रनई ग्राम की और भी परंपराएं, क्या अब ग्राम में होंगे पंचायत चुनाव के लिए मतदान ?

रनई जमींदार परिवार के विकास के भाजपा प्रवेश की बातें जिस तरह लगातार सुनाई दे रही हैं उससे लगता है की बात में सच्चाई है और वह अब ग्राम की परंपरा तोड़ने वाले हैं। अब भाजपा प्रवेश करके वह एक परंपरा तोड़ने ही वाले हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ने के फलस्वरूप सामने आयेगी वहीं वह क्या अब रनई में पंचायत चुनाव में मतदान भी कराएंगे या इसके पक्ष में अपना समर्थन देंगे यह भी देखने वाली बात होगी। रनई में पंचायत चुनावों में मतदान नहीं होता अब यदि विकास भाजपा का दामन थामते हैं तो पंचायत चुनावों में भी मतदान देखने को मिलेगा ऐसा माना जा रहा है।

सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना सामूहिक जिम्मेदारी: एसपी एमसीबी



-संवाददाता- मनेन्द्राह, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

34 वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का जिला स्तरीय समापन गुरुवार को एमसीबी जिला कलेक्टर डी राहुल वेकेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह की उपस्थिति में पंडित दीन दयाल चौक में हुआ। मंच में जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में अधिकतर युवाओं की मृत्यु यातायात नियमों का पालन नहीं करने, तेज गति से वाहन चलाने के कारण होती है। सड़क सुरक्षा नियमों की जागरूकता न सिर्फ युवाओं में बल्कि आमजन में प्रचारित-प्रसारित कि जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली जान व माल की हानि से बचा जा सकें। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा

कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करना न सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी समाज और परिवार में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा कर दिलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना वाहन चालक हेलमेट बेल्ट से बांधकर वाहन नहीं चलाते हैं। दुर्घटना वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग किया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में 16 से 35 आयु वर्ग के युवाओं की होने वाली मृतकों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि चार पहिया वाहन चलाते समय वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें, वाहन तेज गति से न चलाए, गलत दिशा में न चले, मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। और शराब पीकर वाहन न चलाए। उन्होंने

अंतरराज्यीय ऑनलाइन टग गिरोह के खिलाफ कोरिया पुलिस की कार्यवाही, दो आरोपी गिरफ्तार



-संवाददाता- बैकुण्ठपुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले में ऑनलाइन फ्रॉड के एक मामले में कोरिया पुलिस को मिली सफलता दो आरोपी हुए गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक - 32/24 धारा - 420 भा.द.वि. एवं 66(ग)(घ) आईटी एक्ट मामला पंजीबद्ध कर भेजा गया जेल।

पुलिस से जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह

परिहार (भापुरे) के निर्देशन एवं अति0 पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह ठाकुर, एस.डी.ओपी. कविता ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक नक्सल राजेश साहू, थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल किण्डो के मार्गदर्शन में जिले में ऑन लाईन फ्रॉड के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया गया। जिला कोरिया छठ00 पुलिस ने अंतरराज्यीय टग गिरोह को किया गिरफ्तार याना बर्या में अपराध क्रमांक 32/2024 धारा 420 भादवि एवं 66 (ग) (घ) आईटी एक्ट के प्रकरण के प्रार्थी



सोनई सिंह से दर्ज कराया कि कि जीवा हर्बल हेल्थ केयर में लकी ड्रग लगा जिसमें द्वितीय पुरस्कार मिला है दिये गये नंबर पर फोन किया तो लकी ड्रग में मिले गाड़ी चाहिये तो रजिस्ट्रेशन हेतु 5,500 रुपये लगेगा और बीमा के लिये 12,000 रूपया लगेगा और आल इण्डिया परमिट के लिये 25,500 रुपये लगेगा गया था कि अलग अलग आरोपी अलग अलग नंबरों से कॉल कर प्रार्थी से अलग अलग अकाउण्ट में पैसा मांग रहे थे जब प्रार्थी टांगों के झंसे में आकर

जिला प्रशासन की टीम ने एक दिन में रुकवाये तीन बाल विवाह

विवाह होने के अंदेशा से बालिकाओं को संरक्षित किया गया सखी वन स्टाप सेंटर में



-संवाददाता- सूरजपुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

जिला कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण इकाई जिले में बाल विवाह रोकने हेतु सक्रिय है। कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त टीम एलर्ट मोड में है। सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर जाकर छानबीन करती है और सूचना सही पाये जाने पर समझावश की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल के पास आई सूचना की संदर्भण विकासखंड रामानुजगर में बाल विवाह हो रहा है। विवाह की सूचना

जिला कार्यक्रम अधिकारी रमेश साहू को दी जिला कार्यक्रम अधिकारी के त्वरित कार्यवाही के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग, चार्डलड लाईन, पुलिस थाना रामानुजगर की संयुक्त टीम गांव गई जहां मौके पर शैक्षणिक दस्तावेजों का निरीक्षण करने पर शिकायत सही पाई गई। मौके पर विवाह के कार्यक्रम किये जा रहे थे। मण्डप सजा हुआ था। लोग नाच-गा रहे थे। पुलिस सहित संयुक्त टीम को देखकर सभी डर गये। बाल विवाह करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने

की जानकारी परिजनों समेत ग्रामीणों को दी गई। विवाह होने पर दो वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड की कार्यवाही होने की बात बताई गई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में विवाह करने वाले, अनुमति देने वाले सभी के ऊपर कार्यवाही के प्रावधान होने की जानकारी दी गई है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी के साथ समस्त टीम ने गांव में होने वाले विवाहों की जांच की जिसमें गांव में एक 17 वर्षीय बालिका एवं एक 18 वर्ष छः माह के बालक और बाल विवाह होते पाया गया। सभी के यहां कथन पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर यह देखा गया कि बालिका के छोड़ने



पर आज ही विवाह कर देंगे। इस स्थिति में बालिकाओं को विवाह से बचाने के लिए उन्हें ले जाने का पंचनामा तैयार किया गया और महिला स्टाफ के साथ उन्हें सूरजपुर के सखी वन स्टाप सेंटर ले लाया गया। वहीं बालिकाओं को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात् अभिभावकों का कथन, शपथ पत्र लेकर बालिका का उर हो जाने पर ही विवाह किया जायेगा। तब उनके पालकों के सुपुर्द किया जायेगा। बाल विवाह रोकवाने वालों में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, संरक्षण अधिकारी अखिलेश सिंह, चार्डलड लाईन क्राइडनेटर कार्तिक मजूमदार, टीम मेंबर कुमारी

शोतल सिंह, पर्यवेक्षक मानकुवर, सरपंच देव बाई सिंह, पुलिस थाना रामानुजगर से प्रधान आरक्षक सुशील तिवारी, आरक्षक विकास सिंह, देवचन्द पाण्डेय आउटरीच वर्कर हर गोविन्द चक्रधारी उपस्थित थे।

नेशनल लोक अदालत की तैयारी को लेकर समस्त न्यायिक अधिकारियों ने की बैठक

-संवाददाता- सूरजपुर, 15 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशानिर्देशन में गोविन्द नारायण जांगड़े, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर ने आगामी 09 मार्च 2024 को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारी को लेकर समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिसमें लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा विधि में राजीनामा योग्य घोषित सिविल एवं दाण्डिक प्रकरणों, निष्पादन विद्युत विभाग से संबंधित बकाया प्रकरण, नगरनिगम से संबंधित प्रकरण जैसे जल कर मकान कर तथा अन्य कर, बैंक के बकाया से संबंधित लक्षित प्रकरण, टेलीफोन बिल का भुगतान कर उसका निराकरण के संबंध में चर्चा की गई। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बैंक विद्युत एवं नगरपालिका के अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक अदालत के संबंध में चर्चा की गई। जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, तालुका विधिक सेवा प्रतापपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम नागरिकों से यह अपील किये है कि नेशनल लोक अदालत के बारे में अधिक से अधिक लोगों से चर्चा परिचर्चा करे ताकि इस नेशनल लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें। यदि किसी पक्षकार का प्रकरण 09 मार्च को नियत नहीं किया गया है तो ऐसे प्रकरणों में पक्षकार राजीनामा करना चाहते है तो वे 09 मार्च को न्यायालय पर समक्ष उपस्थित होकर सुनवाई रखकर प्रकरण में राजीनामा के आधार पर समाप्त कर सकते है। आगामी नेशनल लोक अदालत में प्री. लिटिगेशन प्रकरण दिनांक 29 फरवरी तक पेश किये जा सकते हैं। वहां उपस्थित अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा प्रकरण में निराकृत किये जाने एवं समय पर लिटिगेशन प्रकरण पेश किये जाने पर जोर दिया गया है।

धर्मान्तरण मामले में आज पोड़ी मोड़ बनारस हाइवे में रहा चक्काजाम

-संवाददाता-
प्रतापपुर, 15 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

प्रतापपुर चंगाई सभा के माध्यम से धर्मान्तरण कराने के मामले का तुल पकड़ने के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने पूर्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर कहा था कि अगर धर्म परिवर्तन करने वाले को ऊपर में सख्त कार्रवाई की नहीं जाती तो चंदौरा थाना चौक पर चक्का जाम करेंगे। उक्त मामला तुल पकड़ने के साथ माहिल आज देखते ही देखते पुलिसिया कार्यवाही नहीं होने के कारण कई हिंदू संगठन के लोगों ने आज स्थानीय चंदौरा थाना चौक के पास लगातार लगातार दो से तीन घंटा बृहद रूप से चक्का जाम कर दिया ज्ञात हो के मुख्य मार्ग अम्बिकापुर

बनारस मार्ग के बीचो-बीच चक्का जाम करने से चारों तरफ से हजारों ट्रक की 5-5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई जिसमें ट्रक सहित बस पिकअप वाहन यात्री वाहन इस चक्का जाम में फसे रहे। पुलिसिया कार्यवाही नहीं होने के विरोध में धर्मान्तरण को लेकर लोगों में भारी आक्रोश फूट गया जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस के ऊपर में अपना भड़पस निकाल कर बताया कि आज 10 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की उक्त धर्म परिवर्तन करवाने वालों के ऊपर में सख्त कार्रवाई नहीं होने से हिंदू संगठन के लोगों में भारी गुस्सा एवं आक्रोश देखा गया, जहां चक्का जाम के समर्थन में सैकड़ों लोग जुड़ते चले गए।



कार्यवाही आश्वासन के बाद समाप्त हुआ हड़ताल

इस दौरान पुलिस एसडीओपी, अरुण नेताम एसडीएम दीपिका नेताम, प्रतापपुर को भी ज्ञापन सौंप कर तत्काल कार्यवाही की मांग करते हुए धर्म परिवर्तन करने वालों के ऊपर में शाम तक कार्रवाई करने का आश्वासन के बाद में, चक्का जाम समाप्त हुआ प्रदर्शन कारियों ने कहा कि अगर शाम तक कार्रवाई नहीं होती है तो फिर से उग्र प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा वहीं पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया के मामला को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाएगी।

तत्काल कार्यवाही की मांग

कार्यवाही को लेकर हिंदू संगठन के लोग निरंतर अड़े रहे इनका कहना था कि तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार जब तक नहीं होगा तब तक से चक्का जाम समाप्त नहीं होगा पुलिस एवं एसडीएम के समझाने के बावजूद भी प्रदर्शनकारी नहीं मान रहे थे चक्का जाम से भारी संख्या में पुलिस मुस्तैयत किए गए थे जहां पुलिस के भी पसीना छूट रहे थे वहीं प्रशासनिक अधिकारी सहित जिले के तमाम पुलिस अधिकारी सहित कई थाना प्रभारी अनुभाग्य अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैयत थे

यह रहे उपस्थित

इस दौरान मुख्य रूप से विरेंद्र शर्मा, मनोज पांडेय, बिट्टू सिंह राजपूत, पूरन राजवाड़े, रुपचंद देवांगन, देवपाल सिंह पैकरा, लाल साय सिंह पावले, डब्ल्यू गुप्ता, रेवती चौकी प्रभारी सुमंत पांडे, खडगावा चौकी प्रभारी योगेंद्र जायसवाल रामकोला थाना प्रभारी मनीष राजवाड़े, तसीलदार पुष्पा राज पात्रे नायब तहसीलदार राधेश्याम तिकी सहित भारी संख्या में लोग। वा ग्रामीण उपस्थित थे।

अस्पताल के भर्ती मरीजों की थाली से पोषण आहार गायब जिम्मेदार कह रहे हैं सब ठीक, मीनू के अनुसार नहीं मिलता है पोषण आहार



-राजेन्द्र शर्मा-
खडगावा, 15 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

एमसीबी जिले के अस्पताल में भर्ती मरीजों को इन दिनों पोषण आहार मीनू के अनुसार नहीं मिलता है शासन की गाइडलाइन के मुताबिक मरीजों को अंडा और दूध अनिवार्य रूप से दिया जाना है लेकिन अस्पताल प्रबंधन को गाइडलाइन से कोई मतलब नहीं है। एमसीबी जिले के अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग हर साल मरीजों को इलाज के साथ उन्हें उच्च गुणवत्ता का भोजन मुहैया कराने के लिए लाखों रुपए खर्च प्रति वर्ष खर्च करती है लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीजों की थाली से पोषण आहार गायब हो चुका है। मरीजों की थाली में सुबह के नाश्ते में मीनू के अनुसार नाश्ता नहीं दिया जाता है।

थाली खाने को दिया जाता रहा है मरीजों को

आप को बता दें कि खडगावा अस्पताल के सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि भर्ती मरीजों को अस्पताल में दिए गए मीनू के अनुसार उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है दाल, चावल, आलू लोकी की सब्जी दी जाती है लेकिन रोटी नहीं दी जाती है। वहीं खाने में गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती है अस्पताल में भोजन को लेकर भर्ती मरीजों में चर्चा का विषय बना रहता है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की और परिजन की माने तो खाने को लेकर उन्हें काफी परेशानी हो रही है। नाश्ते में भर्ती मरीजों को मीनू के अनुसार नाश्ता भी प्राप्त नहीं होता है - वहीं भर्ती मरीजों को सुबह नाश्ते में पोहा कभी हलुआ दलिया मिलता है लेकिन फल और अंडा नहीं मिलता है। दोपहर के खाने में दाल चावल, आलू लोकी मिक्स ज्यादा मिलती है। लेकिन रोटी नहीं मिलती है।

जिम्मेदार की नजर में सब ठीक

अस्पताल में सुबह मरीजों की थाली में मीनू के अनुसार दूध, अंडा और फल शामिल है। दोपहर के खाने में चावल दाल रोटी हरी सब्जी दी जाती है मगर मीनू के अनुसार कुछ भी मरीजों को नहीं मिलता है।

गुड सेमेरिटन व यातायात जागरूकता में सहयोग करने वाले अधिकारी किए गए सम्मानित

सूरजपुर में हुआ 34 वां राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा माह का हुआ समापन



-संवाददाता-
सूरजपुर, 15 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर गुरुवार को ऑडिटोरियम भवन में भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथियों ने गुड सेमेरिटन को सम्मानित कर यातायात व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों को हैसला अफजाई कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया। पूरे देश में 1 माह से चल रहे यातायात सड़क सुरक्षा माह का आज समापन किया गया। आपको बता दें कि कलेक्टर सूरजपुर रोहित ब्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एम.आर.आहिरे, डीएफओ पंकज कमल, भाजपा जिलाध्यक्ष बाबुलाल अग्रवाल व सीएचएमओ डॉ. आर.एस.सिंह के मुख्य आतिथ्य में जिले में आयोजित 34वां राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा माह 2024 का समापन हुआ। जिला सूरजपुर पुलिस द्वारा जिले में

दिनांक 15.01.2024 से 14.02.2024 तक राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी सहित थाना-चौकी प्रभारियों के द्वारा लगातार भीड़-भाड़ वाले चौक चौराहों, स्थानों में पम्पलेट, लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, मालवाहक वाहनों में कभी भी सवारों को हैसला अफजाई कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया। पूरे देश में 1 माह से चल रहे यातायात सड़क सुरक्षा माह का आज समापन किया गया। आपको बता दें कि कलेक्टर सूरजपुर रोहित ब्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एम.आर.आहिरे, डीएफओ पंकज कमल, भाजपा जिलाध्यक्ष बाबुलाल अग्रवाल व सीएचएमओ डॉ. आर.एस.सिंह के मुख्य आतिथ्य में जिले में आयोजित 34वां राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा माह 2024 का समापन हुआ। जिला सूरजपुर पुलिस द्वारा जिले में



दिनांक 15.01.2024 से 14.02.2024 तक राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी सहित थाना-चौकी प्रभारियों के द्वारा लगातार भीड़-भाड़ वाले चौक चौराहों, स्थानों में पम्पलेट, लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, मालवाहक वाहनों में कभी भी सवारों को हैसला अफजाई कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया। पूरे देश में 1 माह से चल रहे यातायात सड़क सुरक्षा माह का आज समापन किया गया। आपको बता दें कि कलेक्टर सूरजपुर रोहित ब्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एम.आर.आहिरे, डीएफओ पंकज कमल, भाजपा जिलाध्यक्ष बाबुलाल अग्रवाल व सीएचएमओ डॉ. आर.एस.सिंह के मुख्य आतिथ्य में जिले में आयोजित 34वां राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा माह 2024 का समापन हुआ। जिला सूरजपुर पुलिस द्वारा जिले में

दिनांक 15.01.2024 से 14.02.2024 तक राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी सहित थाना-चौकी प्रभारियों के द्वारा लगातार भीड़-भाड़ वाले चौक चौराहों, स्थानों में पम्पलेट, लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, मालवाहक वाहनों में कभी भी सवारों को हैसला अफजाई कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया। पूरे देश में 1 माह से चल रहे यातायात सड़क सुरक्षा माह का आज समापन किया गया। आपको बता दें कि कलेक्टर सूरजपुर रोहित ब्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एम.आर.आहिरे, डीएफओ पंकज कमल, भाजपा जिलाध्यक्ष बाबुलाल अग्रवाल व सीएचएमओ डॉ. आर.एस.सिंह के मुख्य आतिथ्य में जिले में आयोजित 34वां राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा माह 2024 का समापन हुआ। जिला सूरजपुर पुलिस द्वारा जिले में

तेज रफ्तार कार सड़क किनारे दीवार में जा घुसी, दो लोग घायल

-संवाददाता-
कोरबा, 15 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

बीती रात जिले में राहस मिल गोदाम के सामने एक तेज रफ्तार कार हदसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि कार पर दो लोग सवार थे, जो शराब के नशे में धुत थे। घटना लगभग 11:00 बजे रात की है, जब यह हदसा हुआ। इस हदसे के बाद राहगीरों के भीड़ एकत्रित हो गई और वाहन में फसे एक व्यक्ति को किसी तरह बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की



लोगों की माने तो कार की रफ्तार काफी तेज थी, जो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाली से पार करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री में जा घुसी। राहगीरों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एयर बैग खुलने की वजह से चालक बच गया, नहीं तो जान भी जा सकती थी। वहीं घटना की सूचना के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल इस हदसे में चालक और एक अन्य सवाथों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।

लोगों की माने तो कार की रफ्तार काफी तेज थी, जो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाली से पार करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री में जा घुसी। राहगीरों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एयर बैग खुलने की वजह से चालक बच गया, नहीं तो जान भी जा सकती थी। वहीं घटना की सूचना के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल इस हदसे में चालक और एक अन्य सवाथों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।

मेडिकल कॉलेज सह जिला चिकित्सालय का कलेक्टर ने निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हेतु दिए आवश्यक निर्देश

-संवाददाता-
कोरबा, 15 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

कलेक्टर अजीत वसंत ने स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय व संबद्ध जिला अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल का कायाकल्प करने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने हेतु आवश्यकताओं की जानकारी ली और कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सवित्र मिश्रा, निगमायुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अविनाश



मेश्राम, सीएमएचओ डॉ. एस.एन. केशरी, अधीक्षक डॉ. गोपाल कंवर, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम के अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने जिला अस्पताल के प्रवेश द्वार से लेकर पूरे अस्पताल परिसर का अवलोकन करते हुए सभी एंटी व एंजिट पॉइंट का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल के पूरे परिसर में मरम्मत योग्य स्थानों का सुधार करने, लीकेज सीपेज की रिपेयरिंग एवं जर्जर भवनों को डिस्मेंटल करने हेतु संबंधित अधिकारियों को क्रमवार निर्देशित किया। कलेक्टर ने चिकित्सालय परिसर के विभिन्न वार्डों, कक्षों का अवलोकन करते हुए विभिन्न क्रियाच्यवन एजेंसी द्वारा किए गए निर्माण कार्य के सम्बंध में जानकारी ली।

बालको थाना द्वारा यातायात दुर्घटना एवं जाम से निपटने जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर

-संवाददाता-
कोरबा, 15 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

कोरबा शहर आद्यौगिक नगर होने से जिले की बायपास रोड ध्यानचंद चौक से परसाभांठा चौक होते हुये रिग रोड रिस्की तक प्रतिदिन हजारों की संख्या में भारी वाहनों का आवागमन होता है जिससे जाम एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। जिससे निजात पाने के लिये पुलिस अधीक्षक के निर्देश प्राप्त कर बालको थाना के द्वारा बालको प्रबंधन को पूर्व में कई बार इसके समाधान हेतु मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से उचित एवं ठोस कदम उठाने निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में बालको थाना प्रभारी नितिन उपाध्याय के नेतृत्व में बालको के प्रमुख अधिकारियों के साथ मिटिंग आयोजित कर पुनः ध्यानचंद चौक से रिस्की चौक तक यातायात को सुगम बनाने, जाम से मुक्त दिलाने के संबंध में पत्र लिखे हैं एवं ठोस कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। उक्त संबंध में बालको प्रबंधन के अधिकारियों ने अगवत कराया कि उनके द्वारा भारी वाहनों की पार्किंग हेतु एस-ड्राइव के पास रूमगड़ा रोड में 100



क्षमता वाला, शर्मा पेट्रोल पंप के सामने रिग रोड में 40 क्षमता वाला एवं प्लांट के अंदर कोल गेट के पास 60 क्षमता वाला भारी वाहनों के लिये नया पार्किंग बनाया है तथा पूर्व में प्लांट के अंदर कोल गेट के पास 70 क्षमता वाला पार्किंग है। ध्यानचंद चौक से रिस्की चौक तक यातायात व्यवस्था हेतु जी 4 एस के 20 सिक्योरिटी गार्ड एवं एक इंचार्ज नियुक्त किया गया है जो 24 घंटे

रोड में रहकर यातायात व्यवस्था की निगरानी रखते हैं। बालको प्रबंधन द्वारा ध्यानचंद चौक से परसाभांठा तक के सड़कों का चौड़ीकरण का काम किया है तथा परसाभांठा चौक से रिस्की चौक तक का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। उक्त मार्ग में राखड़ एवं उड़ने वाली धूल से निजात पाने के लिये 2 कैप स्वीपर की इयुटी लगाई गई है तथा दो वाटर टैंकर

वाहन से पानी का निरंतर छिड़काव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त थाना बालको नगर के द्वारा यातायात व्यवस्था हेतु टीम बनाई बनाई गई है जिसमें प्र.आर. लक्ष्मीकांत खरसन मो. न. 8770134124, आरक्षक हिमांचल कंवर मो.न. 9340723983, आरक्षक अनिल साहू मो.न. 7999589084, आरक्षक हरीश मरावी मो.न.

7987623060 व GYS का सिक्योरिटी इंचार्ज देवधन तिवारी मो.न. 7748841843 शामिल है जिसके संबंध में हेल्पलाइन नंबर को विभिन्न स्थानों में पंपलेट के माध्यम से चर्चा किया गया है। उपरोक्त मिटिंग में नितिन उपाध्याय थाना प्रभारी बालकोनगर के नेतृत्व में बालको प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी एवं प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत खरसन उपस्थित हुए।

<p>न्यायालय लिंक कोर्ट देवनगर तहसील रामानुजगर जिला सूरजपुर ४०११०</p> <p>ईशतहारा</p> <p>४०११०.../४-12/2021-22</p> <p>ग्राम कोर्ट चितकाहीपारा के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका नवलसाय आ०/पति कलसाय जाति गोड़ निवासी ग्राम कोर्ट चितकाहीपारा लिंक कोर्ट देवनगर तहसील रामानुजगर जिला सूरजपुर ४०११० द्वारा आवेदक/आवेदिका अपने माता स्व० झगराहीन का विलम्ब/जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीयन कराने बावजूद अनुपस्थित प्रमाण पत्र, मय अन्य सहायक दास्तावेज के साथ न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया गया है। मृत्यु दिनांक 11/11/1998</p> <p>अतः उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो वे स्वमा अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 21/02/2024 को न्यायालयीन समयवधि में उपस्थित कर दावा/आपति पेश कर सकते हैं। उसके पश्चात दावा आपति में कोई विचार नहीं किया जावेगा।</p> <p>अज दिनांक 07/02/2024 को न्यायालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।</p> <p>नायब तहसीलदार देवनगर जिला-सूरजपुर ४०११०</p>	<p>न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 2024020700093</p> <p>दिष्यः- अ-27 मामले की श्रीणी-राजरा सन- 2023-2024</p> <p>सुभाषनगर प.ह.न. 00017 (हो) पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार-प्रकाश साना, स्या साना, ना बा आवुष साना, अनवेदक पक्षकार- प्रकाश साना, स्या साना, ना बा आवुष साना,</p> <p>ईशतहारा</p> <p>आवेदक रुम्मा साना पति स्व० प्रदीप साना व अन्य निवासी सुभाषनगर, गीरी पेट्रोल पंप के सामने, महापौर गली, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा ४०१०० के द्वारा ग्राम सुभाषनगर स्थित खसरा नंबर 264/2 रकबा ०.93० हे० को उपभयक्ष के मध्य में बटवारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपति हो तो पेशी दिनांक 11/03/2024 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।</p> <p>यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08/02/2024 को जारी किया जाता है।</p> <p>तहसीलदार अम्बिकापुर-सरगुजा</p>
--	---

स्कूलों में 33 हजार से अधिक पदों पर होगी शिक्षकों की सीधी भर्ती

कक्षा पहली से लेकर 12 वीं तक इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए होगा एक सेक्शन

- ▶ प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर होगी शीघ्र भर्ती
- ▶ प्रदेश के विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए मिलेगी मासिक ट्रैवल अलाउंस
- ▶ प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वार्षिक अनुदान राशि में वृद्धि
- ▶ पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को मिलेगी प्रतिमाह 25 हजार रूपए पेंशन
- ▶ छत्तीसगढ़ में प्रभु श्रीराम की गाथा को प्रदर्शित करने प्रधानमंत्री श्री रामलला गाथा केन्द्र का किया जाएगा निर्माण
- ▶ प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय लोककला महोत्सव रायपुर, सिरपुर और रायगढ़ में होगा भव्य महोत्सव

रायपुर, 15 फरवरी 2024 (ए।) छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल के विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 8879 करोड़ 01 लाख 49 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 7387 करोड़ 66 लाख 32 हजार रूपए, उच्च शिक्षा के लिए 1049 करोड़ 08 लाख 90 हजार रूपए, पर्यटन के लिए 218 करोड़ 04 लाख 40 हजार रूपए, संस्कृति विभाग के लिए 90 करोड़ 50 लाख 39 हजार रूपए, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए 49 करोड़ 20 लाख रूपए और राज्य विधानमंडल के लिए 84 करोड़ 51 लाख 18 हजार रूपए की राशि शामिल है।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए घोषणा की कि प्रदेश के स्कूलों में 33 हजार से अधिक पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें व्याख्याता के 2524 पद, शिक्षक 8194 पद और सहायक शिक्षक के 22 हजार 341 पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1086 नये पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए बजट में एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्कूलों के रखरखाव और अधोसंरचना विकास के लिए बजट में 265 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 57 हार्डस्कूल और 39 हार्ड सैफ्टी स्कूलों के लिए नवीन भवन निर्माण का प्रावधान है। मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी शंकर रायपुर को अपग्रेड करते हुए 18 नवीन पदों के सृजन हेतु बजट में एक करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सूरजपुर एवं गरियाबंद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के साथ ही जिला कोण्डागांव, सुकमा एवं बलरामपुर के विकासखण्ड कुसुमी के बाइटे को उन्नत करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाने का प्रावधान है। इस हेतु प्रति संस्था 41 पदों की स्वीकृति प्रदान करते हुए बजट में तीन करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में अच्छे काम-काज और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए नवा रायपुर में प्रशासनिक कम्पोजिट बिल्डिंग प्रारंभ करने के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इस भवन में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, संस्कृत विद्यामण्डल, मदरसा बोर्ड, शिक्षा आयोग, पाठ्यपुस्तक निगम और माध्यमिक शिक्षा मण्डल आदि के कार्यालय संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद

शासकीय विद्यालयों का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के 25 हजार स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में स्मार्ट क्लास के तहत इंटरनेट प्रोजेक्टर की सहायता से शिक्षा प्रदान किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों द्वारा अध्ययन, अध्यापन, शैक्षणिक मूल्यांकन की नियमित एवं त्वरित मॉनिटरिंग के लिए केन्द्रीयकृत विद्या समीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा किया कि सरस्वती सायकल योजना के तहत अब 9वीं कक्षा के सभी छात्रों को निःशुल्क सायकल दी जाएगी। मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति संत शिरोमणि गुरु घासीदास, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति को वीर गुणधर के नाम पर किए जाने की घोषणा की। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इनमें प्राध्यापक के 595, सहायक प्राध्यापक के 2150, क्रीडा अधिकारी के 130, ग्रंथपाल 130 एवं तृतीय श्रेणी के 350 और चतुर्थ श्रेणी के 930 पद शामिल हैं। राज्य के 15 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातक विषय संकाय एवं 23 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर संकाय प्रारंभ करने के लिए बजट में 5 करोड़ 80 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 12 महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 12 करोड़ एवं 9 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 4 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शासकीय महाविद्यालय दुर्गकोट जिला-कांकेर एवं भोपालपुर जिला बीजापुर में छात्रावास भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ रूपए और 50 शासकीय महाविद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए मासिक ट्रैवल अलाउंस देने की सुविधा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। जिसके तहत प्रदेश के तीन लाख विद्यार्थियों को 6000 रूपए प्रतिवर्ष डीबीटी से सीधे उनके खाते में भुगतान की जाएगी। प्रदेश के विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जैसे- यूपीएससी, पीएससी, सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की कोचिंग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।



विधानसभा में उठा पुलिस कर्मियों का भत्ता बढ़ाने का मुद्दा



डिप्टी सीएम ने दिया जवाब

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विधायक चातुरी नंद ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों का वेतन भत्ता एवं सुविधाओं को लेकर प्रश्न उठाया। पुलिसकर्मियों के कई अलाउंस पेंडिंग हैं। जैसे साइकल भत्ता, पुलिसकर्मियों को मात्र 18 रूपए साइकल भत्ता दिया जाता है। 2007 का निर्धारण है, हम अनुविभागीय कमेटी के निर्माण की प्रक्रिया कर रहे हैं। वहीं थुलई भत्ता 60 रूपए मिलता है। गृह भत्ता 1500 रूपए मिलता है। पुलिस विभाग के

हमारे भाई 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न ही ग्रेड पे मिल रहा है न ही भत्ता। इस प्रश्न का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन दिया जाता है। साल में एक बार 8 हजार रूपए कीट के लिए दिया जाता है। बस्तर और संवेदनशील क्षेत्र में 15-20 प्रतिशत वेतन का भत्ता दिया जाता है। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में वेतन का 50 प्रतिशत दिया जाता है। नक्सल ऑपरेशन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के लिए भी मूल वेतन का 50 प्रतिशत भत्ता दिया जाता है। इसी तरह फील्ड, भीड़ में कार्य के दौरान भत्ता, चिकित्सा, मोबाइल एवं अन्य तरह के भत्तों का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विभाग के माध्यम से इस बात का विश्लेषण किया गया है। हम एक अंतर्विभागीय प्रक्रिया के गठन में काम कर रहे हैं।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वार्षिक अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। जिसके तहत शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के लिए 450 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 10 करोड़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के लिए 39 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 44 करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के लिए 2 करोड़ 27 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने संस्कृति विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में पद्मश्री प्रास कलाकारों को प्रतिमाह 25 हजार रूपए पेंशन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय लोककला महोत्सव के नाम से राज्य के तीन स्थानों- रायपुर, सिरपुर, चक्रधर महाराज की भूमि रायगढ़ में भव्य महोत्सव का आयोजन करेंगे। इस आयोजन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को आमंत्रित कर छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में एक सांस्कृतिक रूप से बनेगी। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प मेला को भव्य रूप प्रदान करने बजट में 37 करोड़ रूपए, सिरपुर का सांस्कृतिक विकास के लिए 1 करोड़ 28 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के रायपुर में व्यक्तित्व जीवन काल को चित्रस्मरणीय बनाने उनके निवास स्थान वर्तमान डे-भवन को स्वामी विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 4 करोड़ 80 लाख

रूपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर स्थित पुरखोती मुकागन परिसर में प्रदेश का राजकीय मानव संग्रहालय की स्थापना के लिए 8 करोड़ 64 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों एवं मुख्य पर्यटन स्थलों में गढ़कलेवा का विस्तार कर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खान-पान व्यंजनों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। इसके लिए बजट में 2 करोड़ 12 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कलाकार कल्याण कोषण योजना के तहत राज्य के ख्याति प्राप्त किन्तु अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों एवं कलाकारों और उनके परिवारों के लंबी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना अथवा दैवीय विपत्ती के स्थिति में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 25 हजार रूपए से बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी गई है, वहीं निधन होने पर 25 हजार की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 1 लाख रूपए किया गया है। कलाकारों के मासिक पेंशन को 2000 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। गोड़ी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रभु श्रीराम की गाथा को प्रदर्शित करते

रीपा के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप



गृहमंत्री ने कहा- एजी से कराया जायेगा ऑडिट, सीएस कराएंगे केंद्रों की जांच

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकाल में बने रूरल इंटरैक्टिव पार्क को लेकर विधानसभा में काफी हो-हल्ला हुआ। विधायक धरमलाल कौशिक ने रीपा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा से सवाल किये। प्रोजेक्ट के ऑडिट में 80 लाख रूपये किये खर्च..! धरमलाल कौशिक ने देतेवाड़ा और जशपुर जिले का उदाहरण देते हुए बताया कि करोड़ों रूपये के रीपा केंद्र की स्थापना में 50 से 80 लाख रूपये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में खर्च किया गया। धरमलाल कौशिक के इस सवाल के बाद विधायक अजय चंद्राकर ने रीपा के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किये जाने का गंभीर आरोप लगाया।

विधायक अजय चंद्राकर ने रीपा के नाम पर हुए करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने 600 करोड़ खर्च कर रीपा केंद्र खोले, लेकिन इन केंद्रों से होने वाली कमाई कुछ भी नहीं है।

गृहमंत्री भी रीपा के हालात से संतुष्ट नहीं

अजय चंद्राकर और धरमलाल कौशिक के सवाल पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद कई रीपा केंद्रों में जाकर स्थिति देखी है, कई जगहों पर मशीनें भी नहीं हैं। गृहमंत्री ने रीपा केंद्र के नाम पर हुए खरीदी पर ऑडिटर जनरल से सारी खरीदी के ऑडिट कराये जाने की बात कही। इसके साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश के 300 रीपा केंद्रों की जांच कराये जाने की भी बात कही।

सैंकड़ों रीपा खुले मगर कमाई शून्य

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन काल में प्रदेश में 300 रीपा केंद्र खोले गये। ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान के लिए खोले गये इन रीपा केंद्रों में डीएएफ सहित अन्य विभागीय फंडों के इस्तेमाल कर करीब 600 करोड़ रूपये पूर्ववर्ती सरकार ने खर्च किये थे। इस मुद्दे पर आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रदेश भर के रीपा में विभिन्न मर्दों के फंड से की गई खरीदी की जानकारी मांगी थी। धरमलाल कौशिक के सवाल के साथ ही

निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप

वहीं रीपा के मुद्दे पर विधायक धरमजोत सिंह ने भी सवाल उठाये। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में आनन-फानन में रीपा बनवाये गये। जिसके लिए गांव के सरपंचों पर दबाव बनाकर उनसे हस्ताक्षर कराकर रीपा के नाम पर करोड़ों रूपये की खरीदी की गयी।

भुगतान बकाया, सरपंच तनाव में

धरमजोत सिंह ने कहा कि आज भी प्रदेश के कई रीपा केंद्रों में सामानों का खरीदी का भुगतान नहीं हो सका है। जिसका तगादा लगातार व्यापारी गांव के सरपंच से कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गांव के सरपंच काफी तनाव में हैं और कभी भी वे आत्महत्या कर सकते हैं।

एजी करेंगे खर्च का ऑडिट

विधायकों के आरोपों के बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने रीपा में हुए खर्च का त से ऑडिट कराने के साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन महीने में जांच पूरा कराने की घोषणा किया।

सक्षिप्त खबरें

सुनील कुमार कुजूर रायगढ़ सहकारी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त

रायपुर, 15 फरवरी 2024 (ए।) छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय महानदी भवन के सहकारिता विभाग के उपसचिव पीएस सर्पराज द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के सेवानिवृत्त आईएसएस 1986 बैच के सुनील कुमार कुजूर को राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे अपना कार्यभार ग्रहण तिथि से 11 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त किये गये हैं।

सिरगिट्टी में वेस्ट मटेरियल को जलाने पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर से मांगा जवाब

केमिकल युक्त पॉलिथीन सेवन से मौत के मुंह में जा रहे हैं मवेशी

बिलासपुर, 15 फरवरी 2024 (ए।) सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र की खाली जमीन पर कारखानों के वेस्ट मटेरियल को जलाने से हो रहे प्रदूषण के संबंध में एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के कलेक्टर और पर्यावरण संरक्षण मंडल के सचिव से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र में वेस्ट को जलाने से हो रहे प्रदूषण को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है। इसमें कहा



गया है कि कचरे के डंपिंग जहां की जा रही है वहां मवेशी खाने की तलाश करते हैं और केमिकल युक्त पॉलिथीन का सेवन कर असमय मौत के मुंह में जा रहे हैं।

आए दिन यहां पर मवेशियों के शव दिखाई देते हैं। प्रशासन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी है कि उद्योगों से निकलने वाले कचरे का सुरक्षित तरीके से

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में फेरबदल

4 एसपी और 6 डीएसपी रैंक के पुलिस अफसरों का हुआ तबादला

रायपुर, 15 फरवरी 2024 (ए।) छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है। गृह विभाग के जारी तबादला आदेश के मुताबिक 10 एसपी-डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तबादला आदेश के अनुसार संजय सिंह रायपुर क्राइम ब्रांच के नए डीएसपी होंगे। गृह विभाग ने तबादला आदेश जारी कर दिया है।



अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिस अकादमी, चंद्रखुरी रायपुर, शिवचरण सिंह परियोजना को सुकमा उप पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा मयंक रणसिंग को उप पुलिस अधीक्षक भोपालपट्टनम जिला बीजापुर, राजेश चौधरी को उप पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर, ऐश्वर्य कुमार चंद्राकर को उप पुलिस अधीक्षक कोंडागांव, संजय कुमार सिंह को रायपुर क्राइम ब्रांच उप पुलिस अधीक्षक और भावेश कुमार समर्थ को जिला बस्तर के केशलूर में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई।

राशनकार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाई गई

रायपुर, 15 फरवरी 2024 (ए।) नवीनीकरण के लिए खाद्य छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक

विभाग का नया मोबाईल एप तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट एच टी टी पी एच /खाद्य. सीजी. एन आई सी.आई.एन से इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 25 फरवरी 2024 तक बढ़ाया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयाल दास बघेल ने लोगों की सुविधा को देखते हुए छूटे हुए राशनकार्डधारियों हितग्राहियों का प्राथमिकता से ऑनलाइन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख बढ़ाने के निर्देश खाद्य विभाग को दिए थे। खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। राशनकार्ड आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक विभाग का नया मोबाईल एप तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट एच टी टी पी एच /खाद्य. सीजी. एन आई सी.आई.एन से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारियों अपने मोबाईल में इस एप के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राइड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य प्रदान स्तर पर ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

कभी भी लग सकती है आचार संहिता

रायपुर, 15 फरवरी 2024 (ए।) लोकसभा चुनाव नजदीक है। कभी भी आचार संहिता लग सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले द्वारा जारी फाइनल वोटरलिस्ट में भले ही महिला वोटर की संख्या अधिक है।



वोटरलिस्ट में बढ़कर 1014 हो गई हैं। प्रदेश के 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो औसतन 71.49 प्रतिशत मतदान हुआ था। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 77.78 फीसदी वोट पड़े थे।

दो माओवादी हुए गिरफ्तार

दंतेवाड़ा, 15 फरवरी 2024 (ए।) लगे पुलिस पार्टी ने घेराबंदी कर 02 आईईडी ब्लास्ट की घटना में शामिल दो माओवादियों को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। सीआरपीएफ 231 वाहिनी एवं थाना का संयुक्त बल माओवादियों की सूचना पर रात पर निकली थी. दो सदिध व्यक्ति जगरांजु का ओर से आ रहे थे, जो पुलिस पार्टी को देखकर जंगल की ओर भागने

नियुक्त करे। हाई कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर और पर्यावरण विभाग के सचिव से इस संबंध में शपथ पत्र के साथ जवाब दखिल करने के लिए कहा है।